दैनिक लद्दाख टुडे

वर्षः 01 अंकः 27 | लद्दाख, शुक्रवार 16 अक्टूबर 2026 | पृष्ठः 8 मूल्य 2 रुपए | RNI NO.: LAHIN/26/A7900

संक्षिप्त...

ज्ञानेश कुमार के समर्थन में उतरे 30000 लोग, बयान से तहलका!

नई दिल्ली। सरकार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के समर्थन में 3000 से ज्यादा जेन–जी युवा सड़कों पर उतर आए हैं। इसे देखकर कॉकरोचों के होश उड़ गए हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि एक कॉकरोच के मुकाबले 10,000 देशभक्त सड़कों पर आ गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कॉकरोच जनता पार्टी से परेशान लोगों ने अभिजीत दीपके के परखच्चे उड़ा दिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर अभिजीत दीपके को देखते ही लोगों ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि देश को क्यों खराब कर रहा है? आपको बता दें कि दिल्ली के लोगों के अलावा व्यापारी भी इन कॉकरोचों और विपक्षी दलों से बेहद परेशान हैं। दिवाली आने वाली है। नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो चुका ■ शेष पेज 2...

कठुआ में वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत

लद्दाख टूडे संवाददाता

कठुआ, 15 अक्टूबर। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को कठुआ जिले के दयालाचक–चल्लन रोड पर सल्लान के पास एक वाहन की टक्कर से 58 वर्षीय स्कूटी सवार की मौत हो गई। एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया कि यह हादसा तब हुआ जब दयालाचक–चल्लन रोड पर दयालाचक के पास एक वाहन ने JK08M–4588 नंबर वाली स्कूटी को टक्कर मार दी।

उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्कूटी सवार को हीरा नगर के उप–जिला अस्पताल (SDH) ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कठुआ जिले की हीरा नगर तहसील के परांगोली निवासी राज कुमार (58) ■ शेष पेज 2...

जम्मू के कुंजवानी में वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू, 15 अक्टूबर। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार रात जम्मू नेशनल हाईवे पर कुंजवानी के पास एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जब उसकी बाइक को किसी दूसरे वाहन ने टक्कर मार दी।

एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया कि यह हादसा बुधवार देर रात हुआ, जब जम्मू नेशनल हाईवे पर कुंजवानी के पास एक मोटरसाइकिल सवार को किसी दूसरे वाहन ने टक्कर मार दी।

उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल सवार को जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे 'ब्रॉट डेड' (अस्पताल पहुंचने पर मृत) घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान जम्मू के बबल्याना निवासी सावन थापा के रूप में हुई है।

अधिकारी ने बताया कि कानूनी ■ शेष पेज 2...

----- जम्मू --------
अधिकतम – 42°C
न्यूनतम – 32°C
------ श्रीनगर ------
अधिकतम – 36°C
न्यूनतम – 24°C

लद्दाख की प्रगति सर्वोच्च प्राथमिकता, युवाओं के सशक्तिकरण पर जोरः पीएम मोदी

लद्दाख टूडे संवाददाता

लेह। केंद्र सरकार के लिए लद्दाख का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि इस केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके, नई तकनीक सीखने के अवसर प्राप्त हों और उन्हें काम या पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में न जाना पड़े।

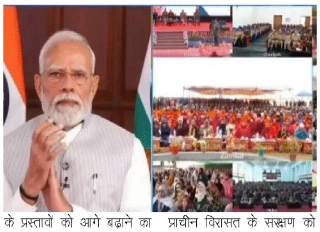

लगभग 3,350 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए, जिनमें हवाई अड्डे का बुनियादी ढांचा और रणनीतिक सड़क संपर्क शामिल हैं, मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य स्थानीय पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हुए इस क्षेत्र में आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है। युवा पीढ़ी के शैक्षिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए, ताकि उन्हें दूसरे शहरों में पलायन न करना पड़े, प्रधानमंत्री ने लेह में एक प्रमुख सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र) बनाने और प्प्ज जम्मू तथा आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्तावों को आगे बढ़ाने का जिक्र किया।

मोदी ने कहा कि ये प्रमुख संस्थान स्थानीय छात्रों को उनके घर के पास ही उन्नत शोध और आधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा, हमारा विशेष ध्यान लद्दाख की नई पीढ़ी पर है। लद्दाख के युवा अब अपने ही क्षेत्र में उच्च शिक्षा, शोध और नए कौशल सीखने के बेहतर अवसर पा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि गुरुवार को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इनसे लद्दाख के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी, कुछ इलाकों में बिजली की सुविधा बेहतर होगी, अन्य जगहों पर पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को मजबूती मिलेगी।

इन परियोजनाओं में लेह के कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपये की लागत से बना एक नया यात्री टर्मिनल शामिल है। इसमें ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए जियोथर्मल (भू–तापीय) ऊर्जा का उपयोग किया गया है, जो लद्दाख के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पर्यावरण में टिकाऊ बुनियादी ढांचे के महत्व को दर्शाता है।

इसके अलावा, मोदी ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) द्वारा बनाई गई 298 किलोमीटर लंबी निम्मू–पदुम–दारचा सड़क, 9 मेगावाट की श्हानुश छोटी ■ शेष पेज 2...

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में 58.26 करोड़ रूपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी

लद्दाख टूडे संवाददाता

गांदरबल। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल जिले में विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने 16.72 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच पूरी हो चुकी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 41.54 करोड़ रुपये की दो नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस तरह, इन सभी परियोजनाओं की कुल लागत 58.26 करोड़ रुपये हो गई है।

इन परियोजनाओं में बेहतर सड़क संपर्क, एक नई स्कूल इमारत, झेलम नदी पर एक पुल और ज़ज़ुना की फल एवं सब्जी मंडी में एक मल्टी–पर्पस ऑक्शन प्लेटफॉर्म (नीलामी मंच) शामिल हैं। इनका उद्देश्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और जिले की बागवानी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने गुज़हामा शिलवत में झेलम नदी पर 39 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले एक पुल की आधारशिला रखी। ■ शेष पेज 2...

एलजी ने जश्न-ए-डल 2026 के सफल आयोजन पर जेएंडके पुलिस को दी बधाई
युवाओं से बड़े सपने देखने और नशा-मुक्त समाज बनाने का किया आह्वान

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जश्न–ए–डल 2026 के सफल आयोजन पर जम्मू–कश्मीर पुलिस को बधाई दी। अपने संदेश में, उपराज्यपाल ने कहा कि खेल मानवीय क्षमता, दृढ़ता और सामूहिक आकांक्षाआ का उत्सव है। खिलाड़ियों के उत्साह और जम्मू–कश्मीर पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि खेल न केवल चैंपियन तैयार करते है, बल्कि युवाओं में संकल्प, धैर्य और साहस भी भरते हैं।

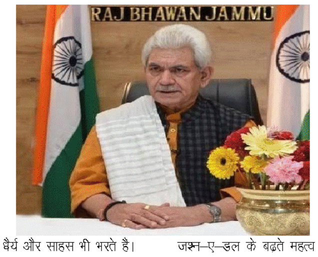

जश्न–ए–डल के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि यह आयोजन अब केवल एक वार्षिक प्रतियोगिता नहीं रह गया है, बल्कि जम्मू–कश्मीर के लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ी एक चेरिशद (प्रिय) परंपरा बन गया है। पिछले कुछ दिनों में, लगभग 600 युवा खिलाड़ियों ने वाटर–स्पोर्ट्स (जल–क्रीड़ा) की 20 विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। इनमें कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, स्कलिंग और पारंपरिक ■ शेष पेज 2...

बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर सरकार के दोहरी सत्ता व्यवस्था वाले तर्क को किया खारिज
कहा–स्पष्टीकरण नहीं, नतीजे मायने रखते

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। बीजेपी के महासचिव सतीश पूनिया ने गुरुवार को जम्मू–कश्मीर सरकार के उस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि श्दो. हरी सत्ता व्यवस्थाश के कारण सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई। पूनिया ने कहा कि सरकार के कामकाज को ऐसे स्पष्टीकरणों से नहीं, बल्कि उसके नतीजों से आंका जाना चाहिए। जम्मू–कश्मीर में पार्टी की एक उच्च–स्तरीय बैठक के लिए आए बीजेपी के प्रदेश

प्रभारी सतीश पूनिया ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि जम्मू–कश्मीर में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव न हो पाने के ■ शेष पेज 2...

गोविंद जायसवाल को उपराज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में किया गया तैनात
श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। जम्मू–कश्मीर सरकार ने आईएएस अधिकारी गोविंद जायसवाल (एजीएमयूटीरू 2007) को उपराज्यपाल के प्रधान सचिव के पद पर तैनात करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, उन्हें श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा 15 अक्टूबर, 2026 को जारी सरकारी आदेश संख्या

1649–जेके(जीएडी) के अनुसार, गोविंद जायसवाल–जो सामान्य प्रशासन विभाग में अपनी ■ शेष पेज 2..

पाकिस्तान की ओर से किसी भी आतंकी हरकत का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा
राजनाथ सिंह ने आपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए नए आतंकी खतरों को लेकर दी चेतावनी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश की ओर से भविष्य में कोई भी आतंकी हरकत होने पर और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने श्ऑपरेशन सिंदूरश, बालाकोट एयरस्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि ये इस बात का सबूत हैं कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ केवल कूटनीतिक निंदा करने के

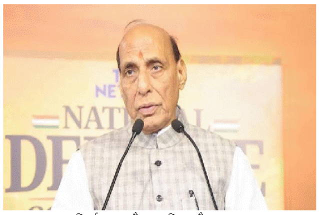

बजाय अब निर्णायक सैन्य कार्रवाई करने का रुख अपना लिया है। यहाँ ■ शेष पेज 2...

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एसएलएससी ने जम्मू-कश्मीर के लिए 13.76 करोड़ रूपये की .षि मशीनीकरण योजना को मंजूरी दी

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। कृषि के आधुनिकीकरण और उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज श्प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाश (पीएम–आरकेवीवाई) के तहत श्कृषि मशीनीकरण उप–मिशनश (समम) के अंतर्गत 2026–27 के लिए 13.76 करोड़ रुपये की संशोधित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को मंजूरी दी।

इस बैठक में कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

के सचिव, योजना विभाग के सचिव, कृषि उत्पादन विभाग के सचिव, कृषि उत्पादन विभाग के विभिन्न विभागों के प्रमुख और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। जम्मू–कश्मीर में कृषि उत्पादकता सुधारने में सिंचाई की अहम भूमिका पर जोर देते हुए, मुख्य सचिव ने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों को उनकी पूरी क्षमता का लाभ दिलाने के लिए सिंचाई योजनाओं पर विशेष ध्यान ■ शेष पेज 2...

मास्टर कारीगर रफ़ीक अहमद सूफी ने कश्मीर का मान बढ़ाया, राष्ट्रीय पुरस्कार जीता

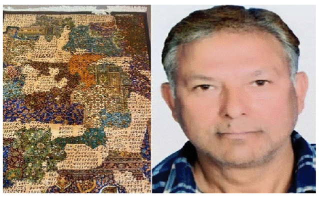

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय ने श्रीनगर के ईदगाह निवासी मास्टर कारीगर रफ़ीक अहमद सूफ़ी को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मिलने पर हार्दिक बधाई दी है। उन्हें यह पुरस्कार भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा हाथ से बुने हुए कालीन ■ शेष पेज 2..

जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश; ताज़ा बर्फबारी के बाद ऊंचे पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके

लद्दाख टूडे संवाददाता

जम्मू। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को जम्मू–कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जबकि कश्मीर घाटी के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रात भर हुई ताज़ा बर्फबारी के कारण हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। इसके चलते प्रशासन ने मुख्य सड़कों से बर्फ हटाने के लिए कर्मचारियों और मशीनों को काम पर लगा दिया है।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जम्मू क्षेत्र के उधमपुर में सबसे ज़्यादा 59.6 मिमी बारिश

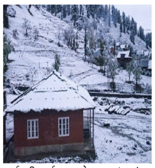

दर्ज की गई। इसके बाद पुंछ (39.5 मिमी), सांबा (34 मिमी), शोपियां (34 मिमी), बारामूला (29 मिमी), कटरा (23.1 मिमी), ■ शेष पेज 2..

नक्सलवाद के खत्म होने से इसके कारण हुए पांच दशकों के दुख-दर्द मिट नहीं जाते : अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन के दौरान दशकों तक लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाई थीं। बस्तर के पुनर्निर्माण और वामपंथी उग्रवाद के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए भाजपा सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए, शाह ने कहा कि केवल नक्सलवाद को खत्म करना ही काफी नहीं है; सरकार को उन पांच दशकों में हुए दुख–दर्द को भी दूर करना होगा, जो विशेष रूप से इस क्षेत्र के गरीब आदिवासी समुदायों ने झेले हैं।

छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के एक कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होते हुए, शाह ने बताया कि 5 से 7 अक्टूबर तक जगदलपुर में आयोजित एक दिव्यांग सहायता कार्यक्रम से 3,600 से अधिक दिव्यांग लोगों को लाभ मिला है, जिनमें अकेले बस्तर के लगभग 1,570 लोग शामिल हैं। इस पहल के तहत नक्सलवाद से प्रभावित लोगों को सहायक उपकरण दिए जा रहे हैं, जिनमें कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, सुनने की मशीनें (हियरिंग एड) और चलने के लिए छड़ियाँ शामिल हैं।

शाह ने कहा, नक्सलवाद के खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि हम इन पांच दशकों के दुख–दर्द को मिटा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को पीड़ितों के जीवन और सम्मान को फिर से संवारने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार को ऐसे प्रयासों में केंद्र की ओर से पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया।

पूर्व उग्रवादियों के पुनर्वास और प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सेवाएं पहुंचाने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए, गृह मंत्री ने बताया कि लगभग 8,526 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। करीब 7,500 लोगों के बैंक खाते खोले गए और 1,625 लोगों को इनाम की राशि दी गई। ■ शेष पेज 2...

हाई कोर्ट ने डल झील में मोटरबोट पर रोक लगाई

लद्दाख टूडे संवाददाता

श्रीनगर। जम्मू–कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने डल झील में ईंधन से चलने वाली मोटरबोट और जेट स्की के इस्तेमाल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

मुख्य न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की खंडपीठ ने बुधवार को मोहम्मद रफीक मीर द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश जारी किया।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, न्याय के व्यापक हित में और सभी पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए, यह निर्देश

दिया जाता है कि संबंधित अधिकारी– एलसीएमए, पर्यटन विभाग और पुलिस– यह सुनिश्चित करें कि डल झील में ईंधन से चलने वाली कोई भी मोटरबोट (चाहे वह शिकारा मोटरबोट हो या जेट स्की) अगले आदेश तक न चलाई जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। आदेश में कहा गया, इसलिए, संबंधित ■ शेष पेज 2...

Created by Universal Document Converter

शेष पेज 1 से

ज्ञानेश कुमार के ...

है। लेकिन विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनों की वजह से व्यापारियों का काम पूरी तरह से ठप रहा। नवरात्रि के पहले तीन शुभ दिन निकल गए। लेकिन इस शुभ मौके पर कॉकरोचों की वजह से दिल्ली के व्यापारियों को अपनी दुकानें बंद रखनी पड़ी। दिल्ली को हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मगर राहुल गांधी अड़ गए हैं कि ज्ञानेश कुमार, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सबका इस्तीफा लेकर रहूंगा। हालांकि राहुल गांधी ने अभी तक जेएनयू के प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम से इस्तीफा नहीं मांगा है।

आपको बता दें कि बिमोल अकोइजम पर यौन उत्पीड़न के आरोप लग चुके हैं। उन्हें जेएनयू से बर्खास्त कर दिया गया है। बहरहाल कॉकरोचों को छोड़िए। असम के लोग सरकार, ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। 3000 से ज्यादा जेन–जी युवा सड़कों पर हैं। इन लोगों का कहना है कि एसआईआर का मकसद इस देश से अवैध घुसपैठियों को लात मारकर भगाने का है और हम इसका समर्थन करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड आदमी हो गए हैं। सत्ता की भूख के लिए उन्होंने देश को अराजकता की तरफ धकेल दिया है। बहरहाल इसी बीच ज्ञानेश कुमार का एक बयान फिर तहलका मचा रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि ज्ञानेश कुमार का यह वो बयान है जिसका जवाब आज तक राहुल गांधी नहीं दे पाए। 400 दिनों से ज्यादा समय बीत चुका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी द्वारा वोटर लिस्ट पर लगाए गए धांधली के आरोपों पर यह कहा था कि राहुल गांधी अपने आरोपों के समर्थन में सात दिनों में सबूत दें हलफनामा दाखिल करें नहीं तो देश से माफी मांगे। लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिए।

अब तो राहुल गांधी यह बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि वोट चोरी हुए हैं। सबूत अब मैं नहीं दूंगा पीएम मोदी देंगे। 17 अगस्त 2025 को ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है। लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या और इन सबके समक्ष सारे मीडिया के समक्ष यह कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने दो बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे। संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं अगर सात दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वह फर्जी हैं। इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगे।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ...

इस पुल से स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन बेहतर होने की उम्मीद है। इसके अलावा, उन्होंने फल और सब्जी उत्पादकों के लिए व्यापार सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से ज़जुना की फल एवं सब्जी मंडी में 2.54 करोड़ रुपये की लागत वाले एक मल्टी–पर्पस ऑक्शन प्लेटफॉर्म की भी आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ने पांच पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें तहसील बाग को लार बाईपास से जोड़ने वाली सड़क और यानिहामा को डेंजरपोरा से जोड़ने वाली सड़क; दार मोहल्ला वट्टलबाय से डेंजरपोरा तक की सड़क और उससे जुड़ी अन्य सड़कें; हाई स्कूल गोगजीगुंड की दो मंजिला इमारत; फतेहपोरा डाक बंगले से गाडूरा पुल तक चौड़ी और अपग्रेड की गई सड़क; तथा झेलम नदी के किनारे पाटी वास्कुरा से खारबाग बांध तक की सड़क शामिल हैं। 16.72 करोड़ रुपये की कुल लागत से पूरे हुए इन कार्यों से स्थानीय संपर्क और शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार होने की उम्मीद है।

अपने दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने श्रीनगर रिंग रोड परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही, मनिगाम स्थित डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर्यावरण पार्क में इंजीनियरों ने उन्हें पांडाच–मनिगाम खंड पर चल रहे निर्माण और अपग्रेडेशन कार्यों के बारे में जानकारी दी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 290.51 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित की जा रही 12.115 किलोमीटर लंबी राजमार्ग परियोजना में, मौजूदा दो–लेन सड़क को चार–लेन वाले दोहरे मार्ग (डुअल कैरिजवे) में अपग्रेड करना शामिल है। इस परियोजना में पुल, एक फ्लाईओवर, पुलिया (कलवर्ट) तथा सर्विस और स्लिप सड़कें शामिल हैं, और इसे मई 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने गांदरबल में सिंध रिवर फ्रंट और म्युनिसिपल टाउन हॉल में चल रहे कार्यों का भी जायजा लिया। 4.83 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से विकसित किए जा रहे सिंध रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के पहले चरण में एक सुरक्षा दीवार, लैंडस्केपिंग, पक्का पैदल मार्ग, एक व्यू–पॉइंट, एक पैटियो कैफे और सजावटी लाइटिंग शामिल हैं।

3 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत टाउन हॉल के अपग्रेड और विस्तार प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने और इसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि आम जनता को जल्द से जल्द ये सुविधाएं मिल सकें।

लद्दाख की प्रगति ...

जलविद्युत परियोजना और 66 केवी डबल–सर्किट दाह–हानु–खालत्सी ट्रांसमिशन लाइन को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने लेह के सिंधु घाट पर भारत के पहले श्पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्कश (प्राचीन शैल–चित्र संरक्षण पार्क) और श्प्रोजेक्ट हिम सरोवरश के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन किया।

मोदी ने कहा, आज, लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इन परियोजनाओं के लिए लद्दाख के सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इन परियोजनाओं से जुड़े सभी इंजीनियरों, श्रमिकों और स्थानीय साथियों को भी बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से बीआरओ के साथियों की सराहना करता हूं। न्यायिक पहुंच को आसान बनाने की लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय मांग पर बात करते हुए, मोदी ने कहा कि सरकार ने अगस्त में लद्दाख के लिए एक हाई कोर्ट बेंच स्थापित करने को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण संस्थागत जरूरत को पूरा करने से नागरिकों के लिए प्रशासन और कानूनी सहायता, दोनों ही आसान हो जाएंगे।

उन्होंने कहा, इससे प्रशासन के साथ–साथ न्याय प्रणाली तक पहुंच भी आसान हो जाएगी। मोदी ने यह भी कहा कि लद्दाख में खेलों के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यहां के युवा आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि लद्दाख में नई खेल नीति के जरिए खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलें, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई उपलब्धियां हासिल कर सकें। होटलों, रेस्तरां, होमस्टे और स्थानीय शिल्प के लिए आधुनिक व्यापार को बढ़ावा देने में डिजिटल कनेक्टिविटी की भूमिका पर जोर देते हुए, मोदी ने इस क्षेत्र के दूर–दराज के इलाकों में श्भारतनेटश और हाई–स्पीड इंटरनेट के विस्तार के बारे में विस्तार से बताया।

उन्होंने कहा कि ई–गवर्नेंस तक आसान पहुंच, युवाओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा और स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, आज, ऑनलाइन व्यापार आय के नए रास्ते खोल रहा है।

कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत का पहला ऐसा टर्मिनल है, जिसमें जियोथर्मल हीटिंग (भू–तापीय ताप) की सुविधा मौजूद है। उन्होंने कहा, यह टर्मिनल लद्दाख के पर्यटन क्षेत्र में भी नई ऊर्जा लाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि जमीनी स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती 40 से अधिक गांवों को अपग्रेड किया जा रहा है।

एलजी ने जश्न ...

शिकारा दौड़ शामिल थीं, जो इस क्षेत्र की खेल क्षमता और जीवंत वाटर–स्पोर्ट्स संस्कृति को दर्शाती हैं।

उपराज्यपाल ने खिलाड़ियों से बिना किसी सीमा के बड़े सपने देखने और पूरी लगन व ईमानदारी के साथ उत्कृष्टता हासिल करने की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया। जम्मू–कश्मीर पुलिस की पहल के जरिए तैयार हुए खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि युवा खिलाड़ी एक गौरवशाली विरासत के उत्तराधिकारी हैं और केंद्र शासित प्रदेश के खेल भविष्य के राजदूत हैं।

दृढ़ता, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के महत्व पर जोर देते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि अगर संकल्प और लगन के साथ सामना किया जाए, तो कोई भी चुनौती ऐसी नहीं है जिसे पार न किया जा सके। उपराज्यपाल ने खिलाड़ियों और नागरिकों से एक स्वस्थ और नशा–मुक्त समाज बनाने में योगदान देने का भी आह्वान किया। यह रेखांकित करते हुए कि खेल युवाओं के सशक्तिकरण के लिए एक रचनात्मक मार्ग प्रदान करते हैं, उपराज्यपाल ने कहा कि श्जश्न–ए–डलश जैसी पहल युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र–निर्माण, रचनात्मकता और सकारात्मक सामाजिक बदलाव की दिशा में ले जाती हैं।

जम्मू–कश्मीर पुलिस के शसिविक एक्शन प्रोग्रामश और युवाओं पर केंद्रित पहलों जिनमें रन फॉर यूनिटी और आगामी पैडल फॉर पैराडाइज रैली शामिल हैं–की सराहना करते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि इन प्रयासों ने आपसी विश्वास, सामुदायिक भागीदारी और युवाओं की सक्रियता को मजबूत किया है। पदक विजेताओं को बधाई देते हुए, उपराज्यपाल ने उनसे विनम्र बने रहने का आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने अन्य प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वे असफलताओं को भविष्य की सफलता की सीढ़ी के रूप में देखें। अपने संदेश में, उपराज्यपाल ने विश्वास जताया कि जम्मू–कश्मीर का वाटर–स्पोर्ट्स इकोसिस्टम लगातार आगे बढ़ेगा, जिससे आने वाले वर्षों में युवा खिलाड़ियों के लिए और अधिक अवसर पैदा होंगे।

हाई कोर्ट न ...

अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि आज के समय में जब झीलों का अस्तित्व एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है, तो ऐसी गतिविधियों को रोकना जरूरी है जिनसे प्रदूषण फैलता हो।

कोर्ट ने कहा, यह महत्वपूर्ण होगा कि जो भी नीति बनाई जाए, वह पर्यटन गतिविधियों और प्रदूषण के बीच संतुलन बनाए रखे, और इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए एक समान नियम हो। खंडपीठ ने सुझाव दिया कि टूर ऑपरेटरों की जरूरतों और झील के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए सोलर बोट और इलेक्ट्रिक बोट एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं।

कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन सेवाओं, कानून–व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा कार्यों में इस्तेमाल होने वाली नावों को इस आदेश से छूट दी गई है। इससे पहले सरकार को मोटर चालित नावों के लिए एक व्यापक नीति पेश करने का निर्देश दिया गया था। खंडपीठ ने कहा कि (वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता) मोहसिन कादरी इस बात की जांच करेंगे कि क्या पूरी तरह से मोटर चालित नावों की जगह सोलर या इलेक्ट्रिक इंजन वाली नावों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।

नक्सलवाद के खत्म ...

बताया कि 7,882 लोगों को प्रोत्साहन राशि दी गई, 455 लोगों को नौकरियां मिलीं और 129 लोगों को जमीन आवंटित की गई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा शिविरों को सेवा केंद्रों और सामुदायिक सुविधाओं में बदल दिया जाएगा, जिससे सरकारी अधिकारी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और विकास की अन्य जरूरतों पर ध्यान दे सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जिन जगहों पर कभी हमारे सुरक्षाकर्मी आपकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे, अब उन्हीं जगहों पर भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी एक विकसित बस्तर की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये केंद्र बच्चों की स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जरूरतों, युवाओं के रोजगार से जुड़ी चिंताओं और आदिवासी समुदायों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे। शाह ने राज्य सरकार की बस्तर ओलंपिक, बस्तर पांडुम और नियद नेल्लानार जैसी पहलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इनका उद्देश्य आदिवासी संस्कृति को पुनर्जीवित करना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जीवन बहाल करना है।

बीजेपी ने जम्मू–...

लिए बीजेपी जिम्मेदार है। पार्टी की बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, सरकार को ही तय करना है कि वह इसे कैसे समझाती है, क्योंकि जनादेश उन्हें मिला, वे सत्ता में आए और उन्होंने ही वादे किए थे। उन्होंने कितने वादे पूरे किए और कितने पूरे नहीं कर पाए, इसे किसी बहाने से छिपाया नहीं जा सकता। असल मायने में तो नतीजे ही अहम होते हैं।

सरकार के इस दावे पर कि दोहरी सत्ता व्यवस्था (चुनी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन) के कारण वह पिछले दो वर्षों में अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, पूनिया ने कहा, जम्मू–कश्मीर की जनता इन दो वर्षों के नतीजों को अच्छी तरह जानती है। पूनिया ने कहा कि सरकार को जनता का जनादेश मिला था, वे सत्ता में आए और उन्होंने वादे किए थे; इसलिए उनके कामकाज को स्पष्टीकरणों के बजाय नतीजों के आधार पर परखा जाना चाहिए।

पंचायत चुनाव न हो पाने के लिए सरकार द्वारा बीजेपी को जिम्मेदार ठहराए जाने पर उन्होंने कहा, हम (बीजेपी) कैसे जिम्मेदार हैं? जम्मू–कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव कराने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू की थी और पार्टी ने इसे बहुत प्रभावी ढंग से आगे भी बढ़ाया।

उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में ही पहली बार जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव कराए गए थे। इसलिए, इस तरह के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। बीजेपी की संगठनात्मक बैठकों और विभिन्न प्रकोष्ठों (सेल्स) की बैठकों के बारे में बात करते हुए, पूनिया ने कहा कि लंबे समय बाद पार्टी को जम्मू–कश्मीर में एक अच्छा जनादेश मिला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू–कश्मीर की समृद्धि और विकास के लिए काम करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार के गवर्नेंस मॉडल का हवाला दिया।

गोविंद जायसवाल का ...

नई तैनाती के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे–को प्रशासनिक हित में उपराज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जायसवाल अपने मौजूदा दायित्वों के साथ–साथ, अगले आदेश तक श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

यह आदेश उपराज्यपाल के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग, सिविल सचिवालय, श्रीनगर द्वारा जारी किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्ति है, जिसके तहत जायसवाल अब उपराज्यपाल कार्यालय का हिस्सा होंगे और साथ ही उन्हें श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड की अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

पाकिस्तान की ओर स ...

एक रक्षा सम्मेलन (डिफेंस कॉन्क्लेव) को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट एयरस्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य अभियान नहीं थे; ये देश की रणनीति में आए एक बड़े बदलाव को दर्शाते हैं। अब भारत केवल कूटनीतिक निंदा तक सीमित नहीं है, बल्कि आतंकवाद को उसकी जड़ से खत्म करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प को दोहराते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि शांति बनाए रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुरक्षा खतरों का जवाब देने में असमर्थता या अनिच्छा नहीं समझा जाना चाहिए।

उन्होंने जोर देकर कहा, भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी समझने की गलती न करें। हम अपनी संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सिंह ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा बातचीत, सह–अस्तित्व और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करती है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए ताकत, तैयारी और आक्रामकता का सामना करने की क्षमता का होना जरूरी है। उन्होंने कहा, शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अडिग है, फिर भी हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा भारत बनाना है जो शांति की वकालत तो करे, लेकिन सुरक्षा के मामले में पूरी तरह सतर्क रहे और अपनी संप्रभुता, अखंडता तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हो। बदलते सुरक्षा माहौल का जिक्र करते हुए, सिंह ने कहा कि आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है। अब खतरे केवल संगठित नेटवर्क तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें श्लोन–वुल्फश (अकेले हमला करने वाले) और जिसे उन्होंने व्हाइट–कॉलर आतंकवाद कहा, वे भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों और नागरिकों से अपील की कि वे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और हमलों को रोकने के लिए अधिक सतर्क रहें।

सुरक्षा के बदलते परिदृश्य को समझाते हुए, उन्होंने 5डी सुरक्षा खतरे का जिक्र किया–डिसइन्फॉर्मेशन (गलत सूचना), डिस्टेबिलाइजेशन (अस्थिरता), डिसरप्शन (बाधा), डिसेप्शन (धोखा) और डिस्ट्रक्शन (विनाश)। उन्होंने चेतावनी दी कि हाइब्रिड, हाई–टेक और हाइपर वॉरफेयर (अत्याधुनिक युद्ध) के कारण खतरों का पता लगाना और उनका मुकाबला करना कहीं अधिक जटिल हो गया है। रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया कि 2014 के बाद से, अधिकांश आतंकवादियों की ष्शेल्फ लाइफष (सक्रिय रहने की अवधि) घटकर एक साल से भी कम रह गई है। सुरक्षा बल उन्हें भारत के खिलाफ हथियार उठाने के एक साल के भीतर ही खत्म कर देते हैं।

कठुआ में वाहन ...

के रूप में हुई है।

कानूनी औपचारिकताओं के लिए शव को मुर्दाघर में रखा गया है, और पुलिस ने घटना का संज्ञान ले लिया है।

जम्मू के कुंजवानी ...

औपचारिकताओं के लिए शव को ळड्ड जम्मू के मुर्दाघर में रखा गया है और पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लिया है।

मुख्य सचिव की ...

देने की जरूरत है।

उन्होंने कृषि उत्पादन विभाग को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), ड्रिप सिंचाई और कमांड एरिया डेवलपमेंट (क्षेत्र विकास) जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि ये पहल पानी के कुशल उपयोग, सिंचाई के दायरे को बढ़ाने और कृषि भूमि का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुख्य सचिव ने जोर दिया कि कृषि दक्षता बढ़ाने, फसल उत्पादकता में सुधार करने और जम्मू–कश्मीर की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मशीनीकरण और सिंचाई दोनों को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) द्वारा मंजूर की गई इस योजना का उद्देश्य जम्मू–कश्मीर में आधुनिक कृषि मशीनों तक पहुंच बढ़ाना, कामकाज की दक्षता में सुधार करना और तकनीक पर आधारित खेती को बढ़ावा देना है। भारत सरकार द्वारा तय की गई वित्तीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध संसाधनों को तर्कसंगत बनाकर और उन्हें एक साथ मिलाकर इस संशोधित योजना को तैयार किया गया है। इस योजना का मकसद कृषि और बागवानी क्षेत्रों में मशीनीकरण को बढ़ावा देना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ सभी क्षेत्रों को समान रूप से मिले और अलग–अलग सामाजिक–आर्थिक वर्गों के किसानों को लक्षित सहायता मिल सके। इस अवसर पर, एसीएस, एपीडी डॉ. आशीष चंद्र वर्मा ने बताया कि कुल 1,376 लाख रुपये के बजट में से 960 लाख रुपये कृषि क्षेत्र के लिए और 416 लाख रुपये बागवानी क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं।

उन्होंने आगे बताया कि कृषि क्षेत्र के आवंटन में कश्मीर डिवीजन के लिए 505 लाख रुपये और जम्मू डिवीजन के लिए 455 लाख रुपये शामिल हैं। बागवानी क्षेत्र के तहत, कश्मीर डिवीजन के लिए 215 लाख रुपये और जम्मू डिवीजन के लिए 201 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, इस योजना में सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए 1,116.63 लाख रुपये, जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) के तहत 147.39 लाख रुपये और अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) के तहत 111.98 लाख रुपये का प्रावधान है। पीएमडीडीकेवाई बजट के तहत आकांक्षी जिलों के लिए 118.62 लाख रुपये का विशेष आवंटन किया गया है, जिसमें किश्तवाड़ जिले के लिए 92.45 लाख रुपये और बारामूला जिले के लिए 26.17 लाख रुपये शामिल हैं।

मास्टर कारीगर रफ़ीक ....

(हैंड–नॉट्टेड कार्पेट) की श्रेणी में दिया गया है।

सूफी 2025 में इस श्रेणी के लिए जम्मू–कश्मीर से एकमात्र पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने यह पुरस्कार एक ऐसे कालीन के लिए जीता है, जिसमें बारीक फूलों के डिज़ाइन, पारंपरिक वास्तुकला के पैटर्न और सुलेख (कैलिग्राफी) के तत्व शामिल हैं। आज यहाँ जारी एक प्रेस बयान में, विभाग के एक प्रवक्ता ने मास्टर कारीगर की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के प्रसिद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा, यह सम्मान उनकी असाधारण कारीगरी और हाथ से कालीन बुनने की पारंपरिक कला में उनके योगदान को मान्यता देता है। उन्होंने आगे कहा कि इससे घाटी के कालीन उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा।

कश्मीर के हाथ से बुने हुए कालीन सदियों पुरानी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें बेहतरीन बुनाई तकनीक के साथ–साथ विशिष्ट डिज़ाइन और श्तालीमश (बुनाई के लिए विशेष निर्देश) का मेल होता है। इसी कारण, इसके मूल स्थान को देखते हुए, 2016 में इसे जीआई (भौगोलिक संकेतक) टैग प्रदान किया गया था।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सूफी के काम को मिली यह मान्यता, इस पारंपरिक कला की निरंतर उत्कृष्टता और प्रासंगिकता को फिर से साबित करती है। उन्होंने कहा, निदेशालय पूरे क्षेत्र के कारीगरों को इस उपलब्धि से प्रेरणा लेने और गुणवत्ता तथा कलात्मकता के उन मानकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कश्मीरी हस्तशिल्प की पहचान हैं। दिसंबर 2026 में एक औपचारिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें अन्य विजेताओं के साथ–साथ रफ़ीक अहमद सूफी को भी सम्मानित किया जाएगा।

जम्मू–कश्मीर के कइ ...

रामबन (17 मिमी), अनंतनाग (16 मिमी), कुलगाम (18 मिमी) और जम्मू (7.6 मिमी) में बारिश हुई।

अधिकारियों ने बताया कि जम्मू में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) जैसे हालात बन गए।

घाटी के कई हिस्सों में भी रात भर बारिश होती रही, जो गुरुवार सुबह तक जारी रही। इस दौरान क्षेत्र के ज़्यादातर हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को पूरे जम्मू–कश्मीर में बारिश और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लगातार तीसरी रात रुक–रुक कर बर्फबारी हुई। सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों और गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में पहाड़ और मैदान बर्फ की सफेद चादर से ढके नज़र आए।

बर्फबारी के कारण कुछ महत्वपूर्ण सड़कें बंद हो गईं, जिनमें मुगल रोड भी शामिल है। यह सड़क घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने वाला एक वैकल्पिक मार्ग है।

प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटाने के लिए कर्मचारियों और मशीनों को तैनात कर दिया है। बर्फ हटने के बाद इन रास्तों पर फिर से यातायात बहाल कर दिया जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक, पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण घाटी में तापमान काफी गिर गया है। दिन का तापमान सामान्य से लगभग 3–9 डिग्री सेल्सियस नीचे है, जबकि न्यूनतम तापमान में 1–3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जम्मू में अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोनमर्ग में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक पहलगाम से कोई डेटा उपलब्ध नहीं था। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू संभाग के भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और कठुआ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिससे इस क्षेत्र के पहाड़ी जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बन गई है।

मौसम विभाग ने घाटी में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का अनुमान जताया है। इसके साथ ही, कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने और ओले गिरने की भी संभावना है। विभाग के अनुसार, मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। 16 अक्टूबर को कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए हल्की बारिश हो सकती है, जिसके बाद 24 अक्टूबर तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है। जम्मू क्षेत्र में, ऊंचाई वाले इलाकों–जिनमें प्रमुख पहाड़ी दर्रे और सड़कें शामिल हैं–पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। इसलिए, यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं।

मौसम विभाग ने गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहने और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। खराब मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए, किसानों से अपील की गई है कि वे सेब, धान और अन्य फसलों की कटाई के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से स्टोर कर लें। मौसम विभाग ने 16 अक्टूबर को जम्मू क्षेत्र में मौसम के मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान जताया है, हालांकि कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए हल्की बारिश हो सकती है।

HELP LINE

IMPORTANT CONTACT NUMBERS – UT LADAKH

POLICE DEPARTMENT (SPs)

S.NO.	DESIGNATION	NAME OF OFFICER	MOBILE NO.	LAND LINE NO.	EMAIL
1	SP Leh	Shree Raam R (IPS)	8899222100	01982-244031	ssp-leh1@police.ladakh.gov.in
2	SP Nubra	Sh. Stanzin Losal (JKPS)	9419037139 8825045363	–	spnubra@gmail.com (Temporary)
3	SP Changthang	Sh. Syed Zaheer Abass (JKPS)	9797995888	7006368375	sp-changthang@police.ladakh.gov.in
4	SP Sham	Sh. Aijaz Malik (JKPS)	9419923000	6006424325	sp-sham@police.ladakh.gov.in
5	SP Kargil	Sh. Niten Yadav (IPS)	9999339994	01985-232645/232704	sspkargil@police.ladakh.gov.in Fax No. 232645
6	SP Drass	Sh. Istiqaq A. Kacho (JKPS)	8492097235	–	sp-drass@police.ladakh.gov.in
7	SP Zanskar	Sh. Rigzen Sangdup	9419287779 6006164711	–	sp-zanskar@police.ladakh.gov.in

DEPUTY COMMISSIONERS

S.NO.	DESIGNATION	NAME OF OFFICER	MOBILE NO.	LAND LINE NO.	PA TO DC / EMAIL
1	DC Leh	Sh. Romil Singh Donk (IAS)	7982319218	01982-252685	Stanzin – 8494072166
2	DC Kargil	Sh. Rakesh Kumar (IAS)	8604286353	01985-232216	Skarma Gurmat – 9622254259
3	DC Changthang	Sh. Nitish Rajora (IAS)	7053991969	(Temporary)	PA to DC – Kunzes Dolma 6005297553
4	DC Nubra	Sh. Mukul Beniwal (IAS)	8800308665	01982-252049	–
5	DC Zanskar	Sh. Omkar Rajendra Gundage (IAS)	8668894331	–	dc-zanskar@ladakh.gov.in
6	DC Sham	Smt. Kunzes Angmo	9419179108	–	–
7	DC Drass	Sh. Imteeaz Kacho (JKAS)	–	–	–

These numbers are for public assistance and urgent communication only.
FOR ANY EMERGENCY, DIAL 112

Created by Universal Document Converter

जम्मू की रामलीला में अभिनय कर चुके हैं अभिनेता ओम प्रकाश और गायक के.एल. सहगल

डोगरी भाषा में रामलीला का मंचन सराहनीय पहल, धार्मिक गरिमा और मर्यादा बनाए रखना जरूरी

जम्मू (अशोक चाढ़क)। नवरात्रों के अवसर पर जम्मू सहित विभिन्न शहरों और गांवों में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। कई स्थानों पर डोगरी भाषा में भी रामलीला की शुरुआत हुई है, जो स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में सराहनीय पहल है। उम्मीद है कि भविष्य में अधिक से अधिक ड्रामेटिक क्लब डोगरी भाषा में रामलीला का मंचन करेंगे।

बसोहली में खुले मैदान में आयोजित होने वाली रामलीला काफी प्रसिद्ध रही है। वहीं, जम्मू के दीवान बद्रीनाथ मंदिर और रघुनाथ मंदिर की रामलीला का भी विशेष महत्व रहा है। प्रसिद्ध अभिनेता ओम प्रकाश ने भी रामलीला में सीता की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वे हास्य प्रस्तुतियों में भी भाग लेते थे। उनके अभिनय के इसी अनुभव ने आगे चलकर उन्हें मनोरंजन की दुनिया में पहचान दिलाने में मदद की।

प्रसिद्ध गायक कुंदन लाल सहगल, जिन्हें शुरुआती दौर के बड़े सितारों में गिना जाता है, भी जम्मू की रामलीला में अभिनय करते थे। वे रघुनाथ मंदिर की रामलीला में भजन और गीत भी गाया करते थे। सहगल का परिवार मूल रूप से पंजाब से संबंधित था, लेकिन उनके पिता अमर चंद सहगल नवांशहर (आर.एस. पुरा) में तहसीलदार थे और परिवार लंबे समय तक जम्मू में रहा।

डोगरी भाषा में रामलीला का मंचन स्थानीय विरासत को जीवंत रखने का अच्छा माध्यम है। बिशन सिंह दर्दी द्वारा डोगरी में लिखी गई रामायण का नाट्य रूपांतरण भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका कुछ क्लब मंचन कर रहे हैं। आज डिजिटल और आधुनिक तकनीक के दौर में भी रामलीला लोगों के बीच लोकप्रिय है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि आस्था, आदर्शों और जीवन मूल्यों का प्रतीक है। रामायण के प्रत्येक पात्र से समाज को कोई न कोई प्रेरणा मिलती है।

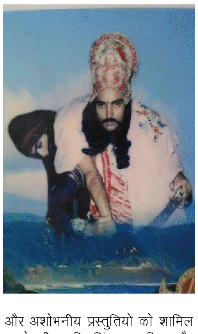

हालांकि, कुछ स्थानों पर रामलीला के दौरान फिल्मी गानों, अनुचित नृत्य और अशोभनीय प्रस्तुतियों को शामिल करने की प्रवृत्ति चिंता का विषय है। धार्मिक मंचन में शराब की बोतलें लेकर नाचना या पात्रों की गरिमा के विपरीत अभिनय करना रामायण और सनातन परंपरा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है तथा दर्शकों की भावनाओं को आहत कर सकता है। प्रत्येक ड्रामेटिक क्लब की प्रबंधन समिति और निर्देशक को चाहिए कि रामलीला में अश्लीलता और फूहड़ता से दूर रहें। पात्रों के अनुरूप वेशभूषा, दृश्य के अनुसार मंच सज्जा, प्रभावी संवाद और बेहतर अभिनय पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मंचन से पहले पर्याप्त रिहर्सल भी जरूरी है।

यदि कलाकार पूरी तैयारी, अनुशासन और श्रद्धा के साथ अपनी भूमिकाएं निभाएं, तो रामलीला न केवल दर्शकों की प्रशंसा प्राप्त करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को भी पहुंचाएगी। रामलीला की वास्तविक सफलता इसी में है कि मनोरंजन के साथ भगवान श्रीराम के आदर्शों और मर्यादा का संदेश भी जन–जन तक पहुंचे।

सीसीआई जम्मू ने नवनियुक्त उपायुक्त मिंगा शेरपा से की मुलाकात, व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा

जम्मू। चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कनिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव गुप्ता और

कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता के साथ जम्मू के नवनियुक्त उपायुक्त मिंगा शेरपा (आईएएस) से मुलाकात कर उन्हें कार्यभार संभालने पर बधाई दी और स्वागत किया। बैठक के दौरान अरुण गुप्ता ने व्यापारियों और आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। उन्होंने त्योहारी सीजन में व्यापारियों और दुकानदारों को अनावश्यक परेशान न करने तथा किसी भी शिकायत पर कार्रवाई से पहले तथ्यों की उचित जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

उन्होंने जम्मू शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम पर चिंता जताते हुए प्रभावी यातायात प्रबंधन और अतिरिक्त पार्किंग जोन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर यातायात व्यवस्था से व्यापारियों, ग्राहकों और आम जनता को राहत मिलेगी। गुप्ता ने प्रधानमंत्री के नशा मुक्त अभियान का समर्थन करते हुए नशे की तस्करी और सेवन के खिलाफ लड़ाई में चौंबर के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने व्यापारियों और युवाओं से प्रशासन के साथ मिलकर नशामुक्त समाज बनाने की अपील की।

उपायुक्त मिंगा शेरपा ने सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि व्यापारिक समुदाय के सदस्यों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा। सीसीआई ने जम्मू के विकास, व्यापारियों के कल्याण और व्यापार अनुकूल वातावरण के लिए प्रशासन के साथ सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने के लिए उठाए जाएं ठोस कदमः अमित कपूर

सरकार बंद करे लालीपाप देने का सिलसिला, कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से करे विचार

जम्मू। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित कपूर ने जम्मू–कश्मीर सरकार से विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को कर्मचारियों को बार–बार आश्वासन देने के बजाय उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान करना चाहिए।

जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित कपूर ने कहा कि दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने के संबंध में सरकार की ओर से कई बार आश्वासन दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी लंबे समय से नियमित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को बार–बार उम्मीदें देकर उनके मसलों को टालना उचित नहीं है।

अमित कपूर ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं

और विभागीय कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें नौकरी की स्थिरता और नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाओं को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने सरकार से अपील की कि दैनिक वेतनभोगियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और उन्हें नियमित करने के लिए स्पष्ट नीति बनाकर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए। अमित कपूर ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों के साथ किए गए वादों को पूरा करना चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि दैनिक वेतनभोगियों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस निर्णय और व्यावहारिक कदम चाहिए।

श्री सदगुरु देव जी महाराज की 36वीं पुण्यतिथि पर रामेश्वरधाम आरएस पुरा में 20 अक्टूबर से शुरू होंगे धार्मिक कार्यक्रम

आरएस पुरा। श्री सदगुरु देव जी महाराज की 36वीं पुण्यतिथि पर रामेश्वरधाम आरएस पुरा में 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक विशाल धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी गुरुवार को सद्गुरगुरु सेवा ट्रस्ट गीता भवन एवं रामेश्वर धाम के प्रमुख स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज की तरफ से दी गई जबकि इस मौके पर संयोजक स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी महाराज के साथ–साथ ट्रस्ट से जुड़े हुए अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। इस मौके पर स्वामी जी ने बताया कि श्री सदगुरु देव जी महाराज की 36वीं पुण्यतिथि पर विश्व अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक रमेश्वरधाम आरएस पुरा में विशाल धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक रोजाना 1.00 से लेकर 4.00 बजे तक भागवत सप्ताह कथा का आयोजन होगा जिसमें स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी महाराज अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को निहाल करेंगे। इसके अलावा

22 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक रात्रि को रोजाना श्री कृष्ण रासलीला का आयोजन होगा जिसमें वृंदावन से आई हुई रास मंडली द्वारा श्री कृष्ण रासलीला का मंचन करेंगे। 26 अक्टूबर को विशाल शोभा यात्रा का आयोजन होगा और 27 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक विराट संत सम्मेलन शुरू होगा जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ–साथ अन्य प्रदेशों से साधु संत हिस्सा लेंगे और अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को निहाल करेंगे। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को विशेष श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन होगा और 30 अक्टूबर को विशाल भंडारे के साथ इस विशाल धार्मिक कार्यक्रम का समापन होगा। उन्होंने क्षेत्र के समस्त श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि वह 20 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस धार्मिक कार्यक्रम में बढ़–चढ़कर हिस्सा लें और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें।

हम भी कम नहीं' सीजन–17 में दिव्यांग प्रतिभाओं ने बिखेरा हुनर

विधायक ने स्कूल भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन

कटड़ा (रोहित शर्मा)। नवरात्र महोत्सव–2026 के अंतर्गत मुस्कान चौरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बुधवार को 'हम भी कम नहीं' सीजन–17 का आयोजन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के आध्यात्मिक विकास केंद्र, कटड़ा में किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे दिव्यांग बच्चों एवं प्रतिभाओं ने संगीत, योग, चित्रकला और अपनी असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों को भावुक और प्रेरित किया। लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा मुख्य अतिथि तथा श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलदेव राज शर्मा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने दिव्यांग प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए

कहा कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की प्रतिभा और सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। इन बच्चों ने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छाशक्ति से साबित किया है कि उचित अवसर और प्रोत्साहन मिलने पर वे किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। उन्होंने ऐसे आयोजनों को समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने तथा दिव्यांगजनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला बताया।ट्रस्ट के अध्यक्ष संदीप मेहरा ने कहा कि 'हम भी कम नहीं' का उद्देश्य दिव्यांग प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और समाज को उनकी क्षमताओं से परिचित करवाना है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन किसी से कम नहीं हैं। उन्हें सहानुभूति के बजाय सम्मान, प्रोत्साहन और समान अवसरों की आवश्यकता है। ट्रस्ट भविष्य में भी दिव्यांग प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे आयोजन करता रहेगा।कार्यक्रम में गुजरात की 'रबर गर्ल ऑफ इंडिया' अन्वी विजय झांझरुकिया ने योग और तैराकी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अहमदाबाद के जय महेश गांगड़िया ने अपनी चित्रकला से दर्शकों को प्रभावित किया, जबकि ६ वर्षा जिग्नेश व्यास ने संस्कृत श्लोकों का गायन कर अपनी असाधारण स्मरण शक्ति का परिचय दिया। जम्मू के दृष्टिबाधित कलाकारों टिकू और अनमोल शर्मा सहित अन्य प्रतिभागियों ने माता के भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया।इस अवसर पर श्राइन बोर्ड के संयुक्त सीईओ डॉ. सतीश शर्मा, सीआरपीएफ की छठी बटालियन के कमांडेंट प्रदीप कुमार गर्ग गोस्वामी, बीएमओ कटड़ा डॉ. रशपाल रसगोत्रा, प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति, नगरवासी और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित रहे।

एनआईटी श्रीनगर ने छात्रों और कर्मचारियों को साइबर खतरों के प्रति किया जागरूक

जम्मू/श्रीनगर। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी श्रीनगर ने गणित के छात्रों, शोधार्थियों और शिक्षण व गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस सत्र में सुरक्षित डिजिटल तौर–तरीकों और साइबर धोखाधड़ी से बचाव पर विशेष ध्यान दिया गया। गणित विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डा. अतेंद्र कुमार द्वारा आयोजित इस सत्र में साइबर हाइजीन, फिशिंग हमलों, पासवर्ड सुरक्षा, सोशल इंजीनियरिंग, डेटा सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफार्म के जिम्मेदार उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

एनआईटी श्रीनगर के निदेशक प्रो. अनुराग मिश्रा ने अपने संदेश में एक ऐसे कैंपस समुदाय के निर्माण पर जोर दिया जो डिजिटल रूप से जागरूक और सुरक्षा के प्रति सचेत हो। उन्होंने तकनीक पर आधारित आज के माहौल में जिम्मेदार आनलाइन व्यवहार के महत्व को रेखांकित किया। गणित विभाग की प्रमुख डा. जम्रूदा जबीन ने भी साइबर धोखाधड़ी को रोकने और उपयोगकर्ताओं को आनलाइन खतरों से बचाने के लिए जागरूकता और सतर्कता के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों को सलाह दी गई कि वे आनलाइन सेवाओं का उपयोग करते समय सतर्क रहें, संदिग्ध लिंक और संदेशों की जांच करें और अपनी तथा संस्थान की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित डिजिटल

तौर–तरीकों को अपनाएं।

इस सत्र का उद्देश्य प्रतिभागियों को आम साइबर खतरों के बारे में बेहतर समझ देना और उन्हें सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि डिजिटल गतिविधियों को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।

इंडियन हाक्स ने जम्मू जिला रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में 23 पदक जीते

जम्मू। इंडियन हाक्स स्पोर्ट्स अकादमी ने श्जिला रोलर स्केटिंग चौंपियनशिप, जम्मू 2026श् में शानदार प्रदर्शन करते हुए 23 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही अकादमी के नौ स्केटर्स अपनी–अपनी आयु श्रेणियों में चौंपियन बने। अकादमी के स्केटर्स ने बेहतरीन गति, कौशल और प्रतिस्पर्धात्मक जज्बा दिखाया। अद्यांश, हनीत, ताबिश और सान्वी ने दो–दो स्वर्ण पदक जीते जबकि तमन्ना, निधान और रुद्र ने एक–एक स्वर्ण पदक हासिल किया। विराज ने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता, वहीं उदय ने एक स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किया।

रजत पदक श्रेणी में सारांश और अद्वैत ने दो–दो रजत पदक जीते जबकि राधिका और समरजोत ने एक–एक रजत पदक

हासिल किया। अयान ने अकादमी के कुल पदकों में दो कांस्य पदक का योगदान दिया। मुख्य संरक्षक और सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता अशोक गंडोत्रा ने पदक विजेताओं को बधाई दी और उनके समर्पण, अनुशासन व कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने स्केटर्स के विकास में बहुमूल्य योगदान देने के लिए कोचों और अभिभावकों के प्रयासों की भी तारीफ की। गंडोत्रा ने युवा खिलाड़ियों को अपना ध्यान केंद्रित रखने, कड़ी मेहनत जारी रखने और आगामी प्रतियोगिताओं में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह प्रदर्शन युवा स्केटिंग प्रतिभाओं को निखारने और जम्मू–कश्मीर में खेल संस्कृति को मजबूत करने के प्रति इंडियन हाक्स स्पोर्ट्स अकादमी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अकादमी अपने खिलाड़ियों को उच्च–स्तरीय प्रतियोगिताओं और भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता पाने के लिए तैयार करने पर लगातार ध्यान दे रही है।

शिवसेना की अष्टमी–नौमी पर अवकाश घोषित करने की मांग

उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन

जम्मू। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की जम्मू–कश्मीर इकाई ने शारदीय नवरात्रि पर अष्टमी और नौमी (महानवमी) के अवसर पर सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की है। इस संबंध में पार्टी ने जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को अलग–अलग ज्ञापन भेजे हैं।

जम्मू के मिश्रीवाला क्षेत्र में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि नवरात्रि हिंदू समाज का प्रमुख धार्मिक पर्व है। अष्टमी और नौमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता की पूजा–अर्चना, व्रत, कन्या पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। ऐसे में इन पावन दिनों पर सरकारी अवकाश होना चाहिए, ताकि श्रद्धालु अपनी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन कर सकें।

साहनी ने कहा कि दशमी पर सरकारी अवकाश घोषित है, लेकिन इस बार अष्टमी

और नौमी पर छुट्टी नहीं दी गई, जबकि पिछले वर्षों में नौमी पर भी अवकाश रहता था। उन्होंने कहा कि जब अन्य समुदायों के प्रमुख त्योहारों पर दो से तीन दिन की सरकारी छुट्टियां घोषित की जाती हैं, तो हिंदू समाज के प्रमुख त्योहारों को भी समान सम्मान मिलना चाहिए।

साहनी ने प्रशासन से फैसले पर पुनर्विचार करने और अष्टमी–नौमी पर अवकाश घोषित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि पूरे जम्मू–कश्मीर में छुट्टी घोषित करना संभव नहीं है, तो कम से कम जम्मू संभाग में इन दोनों दिनों का अवकाश सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर साहनी ने संत एवं सोशल एक्टिविस्ट बाबा चंचल को उनके सामाजिक योगदान और जनहितकारी कार्यों के लिए 'जम्मू योद्धा सम्मान' से सम्मानित किया। बाबा चंचल ने भी नवरात्रि के प्रमुख दिनों पर सरकारी अवकाश की मांग का समर्थन किया।

Created by Universal Document Converter

सम्पादकीय

एक नई कप्तान

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी से हरमनप्रीत कौर का हटना एक अजीब फैसला लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि यह ऐसे समय में हुआ है जब इसे किसी एक खास नजरिए से देखना मुश्किल है। वह टीम के खराब प्रदर्शन के दौर में नहीं हट रही हैं। बल्कि, वह तब कप्तानी छोड़ रही हैं जब उन्होंने भारत को महिला वनडे विश्व कप जिताया हैकृएक ऐसा खिताब जो 2017 में टीम के करीब पहुंचने के बाद से ही भारत की पहुंच से दूर था। इसलिए, इस बदलाव को हरमनप्रीत के प्रदर्शन पर कोई फैसला नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि भारतीय महिला क्रिकेट अब खुद से क्या उम्मीदें रखता है।

हरमनप्रीत के करियर के एक बड़े हिस्से के दौरान, अक्सर यह बहस होती थी कि क्या महिला क्रिकेट को भी पुरुषों के खेल जितनी गंभीरता मिल सकती है। 2017 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी शानदार 171 रनों की पारी इस बदलाव में एक अहम मोड़ थी। फाइनल में इंग्लैंड से मिली हार का दुख आज भी है, लेकिन भारतीय दर्शकों ने एक ऐसी टीम देखी जिससे वे खुद को जोड़ सकेरू एक ऐसी टीम जो सबसे बड़े मंच पर बेहतरीन टीमों को हराने का दम रखती है। आठ साल बाद, जब भारत ने 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व कप जीता, तब भी हरमनप्रीत ही मुख्य केंद्र में थीं। इसके गहरे मायने हैं।

जिस खिलाड़ी ने भारतीय महिला क्रिकेट की महत्वाकांक्षाओं को नई ऊंचाई दी, उसने अब कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप दी है। महिला क्रिकेट की शायद सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, स्मृति मंधाना को सभी फॉर्मेट में कप्तान बनाने का ठब्ब का फैसला, बदलाव के बीच निरंतरता बनाए रखने की एक कोशिश है। मंधाना को किसी संघर्ष कर रही टीम को शून्य से फिर से खड़ा करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। उन्हें एक ऐसी टीम मिली है जिसकी उम्मीदें अब काफी बढ़ गई हैं। इससे उनका काम और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है, न कि आसान। विश्व कप की जीत ने सफलता के पैमाने को बदल दिया है। अब भारत को सिर्फ इस आधार पर नहीं आंका जाएगा कि वह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को चुनौती दे सकता है या नहीं, बल्कि इस आधार पर परखा जाएगा कि क्या वह लगातार उनके साथ मुकाबला कर सकता है।

एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि हरमनप्रीत टेस्ट और वनडे में कप्तान बनी रह सकती थीं, खासकर इसलिए क्योंकि महिला क्रिकेट जैसे विकसित हो रहे खेल में अनुभव का बहुत महत्व होता है। लेकिन, कप्तानी सौंपने के फैसले में भावनाओं को हावी होने देने का एक खतरा भी होता है। 30 साल की उम्र में, मंधाना के पास अभी कई साल हैं, जिनमें वह अपनी कार्यशैली स्थापित कर सकती हैं, युवा खिलाड़ियों को तैयार कर सकती हैं और अपना खुद का नेतृत्व कल्चर विकसित कर सकती हैं। अगर हरमनप्रीत के रिटायरमेंट तक इंतजार किया जाता, तो यह बदलाव बहुत अचानक और कठिन हो सकता था। अब सबसे अहम परीक्षा खुद हरमनप्रीत की है। कप्तानी छिनने का मतलब यह नहीं है कि टीम में उनकी जगह भी चली जाए। हाल के समय में उनकी बल्लेबाजी को लेकर कुछ जायज सवाल उठे हैं, लेकिन भारतीय टीम के पास अनुभवी मैच–विनर्स की इतनी भरमार भी नहीं है कि वह किसी एक खिलाड़ी को आसानी से बाहर कर दे।

अगर वह फिर से निरंतरता हासिल कर लेती हैं, तो कप्तानी की जिम्मेदारियों से मुक्त रहने का यह दौर उनके अंतरराष्ट्रीय करियर को और लंबा खींच सकता है। वहीं, मंधाना के लिए चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि यह बदलाव केवल एक श्व्यक्तित्व परिवर्तनश बनकर न रह जाए। हरमनप्रीत का आक्रामक रवैया और किसी से न डरने का जज्बा, भारतीय टीम के प्रतिस्पर्धी मिजाज को बदलने में बहुत अहम रहा है। शांत स्वभाव वाली मंधाना को अपनी नेतृत्व शैली विकसित करते हुए, उस श्भूखश (जीतने की ललक) को भी बनाए रखना होगा। कप्तानी अब बदल गई है। इस फैसले की असली परख इस बात से होगी कि हरमनप्रीत की विरासत अगली भारतीय टीम के लिए एक श्सीमाश (सीलिंग) बन जाती है, या फिर वह एक ऐसी श्नींवश बनती है जिस पर टीम और भी ऊंचाइयों तक पहुँच सके।

अमेरिका के लिए संकट की घड़ी

दिव्य कुमार सोती

वैसे तो रूस–यूक्रेन युद्ध और इजरायल– अमेरिका–ईरान युद्ध अलग–अलग क्षेत्रों, अलग–अलग कारणों और अलग–अलग समय पर प्रारंभ हुए, परंतु जैसे–जैसे ये लंबे खिंचते जा रहे, एक–दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। अब ये एक ही भू–राजनीतिक शतरंज की बिसात का हिस्सा नजर आने लगे हैं। अनाधिकारिक रूप से ये युद्ध एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। इन्हें अब क्षेत्रीय युद्ध या संघर्ष भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन युद्धों से उत्तरी रूस से कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक प्रभावित हो चुके हैं।

रूस और ईरान ने मिलकर अमेरिका के विरुद्ध सीधे युद्ध की घोषणा भले ही न की हो, परंतु यह युद्ध दोनों आपसी सहयोग से ही लड़ रहे हैं। फरवरी 2026 में ईरान पर इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले से पहले तक ईरान सस्ते, परंतु घातक ड्रोनों की बड़े पैमाने पर रूस को आपूर्ति कर रहा था। अमेरिका से युद्ध छिड़ने पर अपनी जरूरतों के चलते हुए वह ऐसा करने में असमर्थ हो गया तो रूस ने ईरान को घातक ग्रान ड्रोनों की आपूर्ति प्रारंभ कर दी। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में जो वायु प्रतिरक्षा प्रणालियां तैनात की थीं, उनसे जूझने के लंबे अनुभव के आधार पर रूस ने इन ड्रोनों को अधिक उन्नत बनाया था, ताकि वे पश्चिमी रक्षा प्रणालियों को भेद सकें और उसका असर पिछले कई महीनों से ईरान–अमेरिका युद्ध में स्पष्ट नजर आ रहा है।

अमेरिकी तथा इजरायली वायु प्रतिरक्षा प्रणालियां ईरानी ड्रोन हमलों को नाकाम नहीं कर पा रहीं, जिससे युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान और रूस का समन्वय सिर्फ जमीनी युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के आकलन के अनुसार अंतरिक्ष में गश्त कर रहे कम से कम 14 रूसी सैटेलाइट ईरान से वास्तविक काल की भू–स्थानिक, रडार और सिग्नल इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया जानकारियां लगातार साझा कर रही हैं, जिसके चलते ईरानी फौज लगातार खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सफल रही है। इससे अमेरिकी सेनाओं को अच्छा–खासा नुकसान उठाना पड़ा है।

रूस ने ऐसा इसलिए किया है, ताकि अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा रूस के अति महत्वपूर्ण ठिकानों पर यूक्रेन के जरिये कराए गए हमलों का बदला ले सके। साथ ही अमेरिका के हथियार भंडार को इतना कम किया जा सके कि वह यूक्रेन को अधिक सहायता न पहुंचा पाए। इसका असर दिखाई भी देने लगा है। रूस–यूक्रेन युद्ध और अमेरिका–ईरान संघर्ष के एक साथ चलने की वजह से अमेरिकी सेना के पास रक्षा साजोसामान की भारी किल्लत हो गई है। पेंटागन ने चेतावनी दी है कि अगर इस समय कोई और बड़ा वैश्विक युद्ध छिड़ गया, तो अमेरिका के पास हथियारों का स्टाक पूरी तरह खत्म होने का खतरा है। ईरान और उसके समर्थित गुटों के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी सेना को अपनी इन सबसे आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा है, जिसके चलते अमेरिका ने अपने एंटी–बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के लगभग 80 प्रतिशत स्टाक का इस्तेमाल कर लिया है। अमेरिका के आधुनिक पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स का 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत स्टाक खत्म हो चुका है।

अमेरिका के लिए पश्चिम एशिया में वही स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो उसने रूस के लिए यूक्रेन में उत्पन्न की थी। इस संकट के पीछे कम लागत वाले आधुनिक हाइब्रिड युद्ध का गणित है। रूस और ईरान बहुत कम लागत में हर महीने हजारों की तादाद में आत्मघाती ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहे हैं। इसके विपरीत इन्हें विफल करने के लिए अमेरिका के पैट्रियट जैसे रक्षा सिस्टम को बनाने में बहुत जटिल तकनीक और एडवांस गाइडेंस सिस्टम की जरूरत होती है।

अमेरिकी कंपनियां इन मिसाइलों को उतनी तेजी से नहीं बना पा रही हैं, जितनी तेजी से ये युद्ध के मैदान में खर्च हो रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुसार पश्चिम एशिया में मिसाइलें भेजने की वजह से यूक्रेन को पहले के मुकाबले सिर्फ एक–तिहाई एयर–डिफेंस मिसाइलें मिल पा रही हैं। इसका प्रभाव अब चीन के मोर्चे पर भी दिखाई देने लगा है, जहां अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को हथियारों की आपूर्ति में पांच साल तक की देरी होने की चेतावनी दी है। जापान को मिलने वाली टोमाहाक मिसाइलों में दो साल की देरी हो चुकी है। ताइवान भेजी जाने वाली 14 अरब डालर की हथियारों की खेप को बीच में ही रोकना पड़ा है, ताकि अमेरिकी सेना अपने खुद के स्टाक को बचा सके।

जहां ईरान पहले से ही होर्मुज जलमार्ग को बंद करके अपनी ताकत दिखा चुका है, वहीं अब उसके समर्थक यमन के हूतियों के जरिये बाब अल–मंडेब पर कब्जा करके उसने दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्गों पर अपना शिकंजा कस लिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका से हूतियों पर हमले की अपील की थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध और यूक्रेन में खुले मोर्चे के चलते हथियारों की किल्लत के कारण यमन में नया मोर्चा खोलने से मना कर दिया। अमेरिका के पास इतने उन्नत हथियार और प्रतिरक्षा प्रणालियां नहीं बची हैं कि वह एक साथ ईरान से लड़े, यूक्रेन की मदद करे और यमन में भी एक नया मोर्चा संभाल सके।

वैसे तो रूस सीधे तौर पर यमन में हुई इस उथल–पुथल में शामिल नहीं, परंतु उसके चलते मास्को को बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि लाल सागर का रास्ता असुरक्षित होने से कच्चे तेल की कीमतें 106 डालर प्रति बैरल के पार चली गई हैं। इससे आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस के तेल निर्यात की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। इसका सीधा आर्थिक नुकसान पश्चिमी देशों को झेलना पड़ रहा है, जहां ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। इस तरह यह युद्ध न सिर्फ अमेरिकी सैन्य शक्ति की सीमाएं जगजाहिर कर रहा है, बल्कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध तथा सोवियत संघ के विघटन के बाद बनी विश्व व्यवस्था को भी विघटित करता प्रतीत हो रहा है।

मध्य प्रदेश में मामा वनाम मुख्यमंत्री की जंग तेज! शिवराज सिंह चौहान के तीखे तेवर से राज्य की राजनीति गर्माई

नीरज कुमार दुबे

मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों फिर वही पुराना सवाल सिर उठाने लगा है कि क्या सूबे की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान का दखल अब भी उतना ही दमदार है, या मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी अलग लकीर खींचने में जुटे हैं? ऊपर से सब कुछ भाजपा के अनुशासित कुनबे जैसा दिखता है, लेकिन बुधनी के कोसमी गांव से लेकर किसानों की मूंग खरीदी और लाड़ली बहना योजना तक, कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिन्होंने भोपाल के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि ताजा चिंगारी सीहोर जिले के कोसमी गांव से उठी है। यह वही इलाका है, जहां शिवराज सिंह चौहान की बरसों पुरानी राजनीतिक जमीन रही है। गांव में आदिवासी परिवारों के मकान हटाए जाने, फसलों को नुकसान पहुंचने और कुओं को मिट्टी से भरने की शिकायतों पर शिवराज ने अपनी ही पार्टी की सरकार के अधिकारियों को कठघरे में खड़ा कर दिया। उनका रुख साफ था कि सरकार किसी की भी हो, गरीब और आदिवासी परिवारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की और मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात करने की बात कही।

देखा जाये तो राजनीति में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि किसी गांव में मकान टूटे और एक नेता ने नाराजगी जता दी। सवाल यह है कि शिवराज ने यह आवाज उस सरकार के खिलाफ उठाई है, जिसके मुखिया उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री है। मोहन यादव ने भी मामले को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने मुख्य सचिव से जांच कराने और प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आवास तथा भोजन की व्यवस्था करने की बात कही। दूसरी तरफ, कलेक्टर की रिपोर्ट में वन भूमि पर अतिक्रमण और सागौन के पौधों को नुकसान पहुंचाने के आरोप सामने आए। यानी मामला केवल सियासी बयानबाजी का नहीं, बल्कि वन संरक्षण, प्रशासनिक कार्रवाई और आदिवासी परिवारों के अधिकारों का भी है।

लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में हर घटना का एक स्थानीय और एक राजनीतिक अर्थ होता है। कोसमी का मामला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि शिवराज ने जिस इलाके में लंबे समय तक अपनी राजनीतिक पकड़ बनाई, वहीं की घटना पर उनका इस तरह सामने आना कई सवाल खड़े करता है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह केवल अपने पुराने मतदाताओं के प्रति जवाबदेही है, या इसके पीछे भोपाल की सत्ता के साथ तालमेल का कोई बड़ा सवाल भी छिपा है?

इस कहानी का दूसरा सिरा लाड़ली बहना योजना से भी जुड़ता है। शिवराज की राजनीति की पहचान बनी इस योजना ने प्रदेश में महिलाओं के बीच उनकी अलग छवि बनाई। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से योजना के खर्च को भारी बताने वाली टिप्पणी ने पुरानी राजनीतिक विरासत और मौजूदा सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं पर बहस छेड़ दी है। शिवराज के लिए यह योजना महज सरकारी खर्च का हिसाब नहीं, उनकी राजनीतिक पहचान का भी हिस्सा है। वहीं, मौजूदा सरकार के सामने बजट, दूसरी योजनाओं और विकास कार्यों के बीच संतुलन बैठाने की चुनौती है।

तीसरा मोर्चा किसानों का है। मूंग की खरीदी को लेकर जब किसान परेशान हुए, तब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर खरीद तेज करने की मांग की। राज्य सरकार को आखिरकार खरीदी बढ़ाने की मांग पर सहमति देनी पड़ी। देखा जाये तो यहां भी तस्वीर दिलचस्प है। केंद्र में मंत्री शिवराज, राज्य में मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीच में किसान, जिनकी फसल और भुगतान का सवाल सीधे सरकार की जवाबदेही से जुड़ा है। शिवराज का हस्तक्षेप किसानों के लिए मददगार हो सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह राज्य सरकार पर दबाव भी बनाता है।

यही वजह है कि शिवराज बनाम मोहन की चर्चा बार–बार लौट आती है। एक तरफ शिवराज है, जिनकी पहचान लंबे मुख्यमंत्री कार्यकाल, जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश के गांव–गांव में बने पुराने संपर्कों से जुड़ी है। दूसरी तरफ मोहन यादव है, जिन्हें अपनी सरकार की नीतियों, प्रशासनिक फैसलों और नेतृत्व की अलग पहचान स्थापित करनी है। दोनों की भूमिकाएं अलग हैं, मगर प्रदेश की राजनीति में उनका असर एक–दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता।

फिर भी, हर मतभेद को मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई मान लेना जल्दबाजी होगी। भाजपा में संगठन का अपना अनुशासन और केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका है। अभी तक सामने आई घटनाएं प्रशासन, किसान नीति और राजनीतिक विरासत पर मतभेद दिखाती हैय मगर वे किसी औपचारिक सत्ता–संघर्ष को साबित नहीं करतीं।

फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति का असली इम्तिहान बयानों से आगे होगा। कोसमी की जांच में क्या कार्रवाई होती है, प्रभावित परिवारों को क्या राहत मिलती है, लाड़ली बहना योजना को लेकर राज्य सरकार क्या फैसला करती है और किसानों की खरीदी व्यवस्था कितनी दुरुस्त होती है, इन सवालों के जवाब ही आगे की तस्वीर साफ करेंगे।

बहरहाल, भोपाल की सियासत में मामा शिवराज की हुंकार अब भी गूंज रही है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अपने फैसलों से सत्ता पर अपनी पकड़ और नेतृत्व की लकीर खींचने में जुटे हैं। दोनों के बीच सियासी खिंचाव की आहट साफ सुनाई दे रही है, लेकिन इसे खुली जंग का नाम देना अभी जल्दबाजी होगी। असली तस्वीर तब खुलेगी जब यह सामने आये कि कोसमी के मामले में सरकार के कदम क्या होते हैं, लाड़ली बहना योजना पर क्या रुख अपनाया जाता है और किसानों के सवाल पर किसका पलड़ा भारी पड़ता है। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी इरादे सिर्फ बयानों से जाहिर नहीं होते, उनका असली रंग फैसलों में दिखता है। भोपाल में फिलहाल बयान गूंज रहे है, लेकिन निगाहें इस बात पर टिकी है कि अगली चाल कौन चलता है और बाजी किस करवट बैठती है?

Created by Universal Document Converter

अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थाई करने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी देने पर यूनियन ने उनका जताया आभार

उधमपुर, 15 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। अस्थायी कर्मचारियों को स्थाई करने हेतु सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को लेकर अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्यों द्वारा उमर सरकार का आभार जताया गया।

इस अवसर पर सदस्यों ने कहा कि उनकी यूनियन के सदस्य पहले ही श्रीनगर में बैठे हुए थे तथा गत दिन वह भी इसी सिलसिले में श्रीनगर गए था। वहां पर मुख्यमंत्री ने अस्थायी सफाई कर्मियों को मंजूरी दे दी। जिस पर यूनियन सदस्यों ने उनका तथा उनके संबंधित मंत्रियों का आभार जताया, जिन्होंने उनकी लंबित मांग को हल करने में काफी मदद की।

पूरे प्रदेश की तरह उधमपुर में बिजली कटौती नहीं की जा रही है: गुप्ता

बिजली ढांचे को सुधारने हेतु रिपेयरिंग के लिए ही शटडाउन लिए जा रहे हैं

उधमपुर, 15 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। उधमपुर वेस्ट के विधायक पवन कुमार गुप्ता द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग द्वारा बिजली कटौती की जा रही है जबकि उधमपुर जिला में वो कटौती नहीं हो रही है।

उन्होंने कहा कि बिजली ढांचे को सुधारने हेतु रिपेयरिंग के काम के चलते शटडाउन लिए जा रहे हैं। विभाग को हिदायतें दी गई हैं कि त्योहारों के चलते दिवाली तक उसमें भी लोगों को राहत दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शहर की सड़कों के टेंडर हो चुके हैं और जल्द ही शहर के सड़कों की हालत सुधार दी जाएगी।

एस.के.पी.ए. उधमपुर में तकनीक आधारित प्रशिक्षण पर रहेगा मुख्य जोर डॉ. मो. हसीब मुगल

उधमपुर, 15 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। डॉ. मोहम्मद हसीब मुगल आईपीएस ने शेर–ए–कश्मीर पुलिस अकादमी (एस.के.पी.ए.) उधमपुर के निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने गरीब दास आईपीएस एडीजीपी का स्थान लिया है, जिन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है।

पदभार संभालने के तुरंत बाद, निदेशक ने सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने इस प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए टीम वर्क, आपसी समन्वय और सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उच्च स्तर की व्यावसायिकता बनाए रखने और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता को दोहराया।

अपराध के बदलते स्वरूप का जिक्र करते हुए, डॉ. मुगल ने कहा कि पुलिस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कर्मियों को ऐसी पेशेवर दक्षता से लैस करना है, जिससे वे अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने में प्रभावी ढंग से काम कर सकें। उन्होंने बताया कि एसकेपीए में तकनीक आधारित पुलिसिंग और जांच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपराध के नए तरीके सामने आ रहे हैं और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के इस दौर में आपराधिक गतिविधियों में तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

निदेशक ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता में लगातार सुधार करने और स्टाफ तथा प्रशिक्षुओं के बीच अनुशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

उन्होंने प्रशिक्षुओं को नवीनतम तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक कौशल से लैस करने के महत्व को रेखांकित कियाए ताकि एक ऐसी पुलिस फोर्स तैयार की जा सके जो भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम हो।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी भरोसा दिलाया कि स्टाफ और प्रशिक्षुओं का कल्याण उनकी मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।

जिला उधमपुर टेनिस बॉल क्रिकेट चौंपियनशिप 2026 सफलतापूर्वक संपन्न

उधमपुर, 15 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। जिला उधमपुर टेनिस बॉल क्रिकेट चौंपियनशिप का सफल समापन सुभाष स्टेडियम, उधमपुर में हुआ। इस चौंपियनशिप का आयोजन जिला उधमपुर टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किया गया था जबकि इसे जेएंडके स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा प्रायोजित किया गया था।

उधमपुर जिले के विभिन्न जोन से कुल 11 टीमों ने जूनियर और सब–जूनियर बॉयज कैटेगरी में भाग लिया। यह चौंपियनशिप लीग कम नॉकआउट आधार पर खेली गई।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि सुनील वर्मा जिला उधमपुर अध्यक्ष, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थे। आकाश वर्मा प्रोविजनल प्रवक्ता, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मैनेजर, स्पोर्ट्स स्टेडियम उधमपुर ने पहले ही दिन चौंपियनशिप का उद्घाटन किया था। वे ही इस चौंपियनशिप के ऑब्जर्वर भी रहे और उन्होंने विजेताओं, उपविजेताओं और अधिकारियों को ट्रॉफी, मोमेंटो और मेडल प्रदान किए।

वहीं खेल गए अंडर–14 बॉयज के फाइनल में प्रिंसटन इंग्लिश एकेडमी, गढ़ी, उधमपुर व ब्राइट कैरियर हाई स्कूल गढ़ी के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें प्रिंसटन इंग्लिश एकेडमी, गढ़ी की टीम विजेता रही।

अंडर–17 बॉयज के फाइनल मुकाबले में आर्मी पब्लिक स्कूल, धार रोड उधमपुर और दिल्ली पब्लिक स्कूल, रठियान, उधमपुर के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल, धार रोड़ की टीम विजेता रही।

समापन समारोह में कई अतिथियों ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया, जिनमें जतिन सेठी, ईशांग सिंह, सौरव शर्मा शामिल थे।

जिला उधमपुर टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ने उधमपुर स्पोर्ट्स काउंसिल के मैनेजर, जेएंडके टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव, सभी स्कूलों, अभिभावकों, खिलाड़ियों और समर्थकों का आभार व्यक्त किया।

जिला एसोसिएशन ने इस चौंपियनशिप के दौरान आगामी यूटी लेवल चौंपियनशिप 2026 के लिए टीमों का चयन भी किया।

नशे के खिलाफ एकजुटता का संदेश लेकर लखनपुर पहुंची जम्मू–कश्मीर और लद्दाख पुलिस की संयुक्त मोटरसाइकिल रैली

कठुआ, 15 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और नशामुक्त समाज का संदेश लेकर निकली जम्मू–कश्मीर पुलिस और लद्दाख पुलिस की संयुक्त मोटरसाइकिल रैली का गुरुवार को जम्मू–कश्मीर के प्रवेशद्वार लखनपुर में भव्य स्वागत किया गया। एकता दिवस परेड–2026 के तहत निकाली गई इस रैली का मुख्य उद्देश्य 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत करने के साथ–साथ युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना है।

19 जेकेएपी आईआर कठुआ और जिला पुलिस कठुआ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में 19 जेकेएपी आईआर के एसएसपी कमांडेंट अतुल शर्मा, एसएसपी एवं डिप्टी कमांडेंट करणवीर सिंह तथा अतिरिक्त एसपी कठुआ सुनील केसर सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान राजकीय हाई स्कूल लखनपुर के विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेकर राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया। श्रीनगर से 12 अक्टूबर को रवाना हुई इस संयुक्त मोटरसाइकिल रैली के लखनपुर पहुंचने पर प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान रैली के समग्र प्रभारी डीएसपी सज्जाद हुसैन और लद्दाख पुलिस दल के प्रभारी एएसआई नामियल चारोल को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। रैली में शामिल प्रतिभागियों के लिए जलपान और हाई–टी की व्यवस्था भी की गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 19 जेकेएपी आईआर के एसएसपी कमांडेंट अतुल शर्मा ने एकता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत बनाने में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना करते हुए उन्हें देशभक्ति, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 'नशे के खिलाफ जंग' अभियान पर जोर देते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने, इसके दुष्प्रभावों के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने और नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशे जैसी सामाजिक बुराई से निपटने के लिए पुलिस, शिक्षण संस्थानों और आम जनता का सामूहिक प्रयास आवश्यक है। सभी के सहयोग से ही सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने और युवा पीढ़ी के लिए स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारे और नशामुक्त समाज के संकल्प के साथ हुआ। इसके बाद संयुक्त मोटरसाइकिल रैली को एकता दिवस परेड–2026 में भाग लेने के लिए आगे रवाना किया गया।

नवनियुक्त डीसी ने पंजर में जन शिकायत निवारण शिविर का किया आयोजन

लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ–साथ समयबद्ध समाधान के दिए निर्देश

उधमपुर, 15 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। उधमपुर के उपायुक्त अनंत द्विवेदी ने मौंगरी ब्लॉक का व्यापक दौरा किया और पंजर में आयोजित एक जन शिकायत निवारण शिविर की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने जनता की समस्याओं और विकास संबंधी मांगों को सुना।

इस शिविर में अतिरिक्त उपायुक्त प्रेम सिंह, पीओ पोषण सुभाष डोगरा और अन्य जिला अधिकारियों के अलावा पूर्व पीआरआई सदस्य और आसपास की पंचायतों के बड़ी संख्या में निवासी शामिल हुए।

जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान, स्थानीय निवासियों और पीआरआई के पूर्व सदस्यों ने क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं और विकास संबंधी जरूरतों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला।

प्रमुख मांगों में पेयजल आपूर्ति में वृद्धि, क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर शामिल करना,

कैथगली–पंजर सड़क का नवीनीकरण, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती और सद्दल में एक स्वास्थ्य उप–केंद्र की स्थापना शामिल थी।

निवासियों ने जमीनी स्तर पर जेजेएम योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और संचालन, प्रत्येक स्कूल में छोटे खेल के मैदानों के प्रावधान, सरकारी स्कूल पंजर को उच्च माध्यमिक स्तर तक उन्नत करने, क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और पीडब्ल्यूडी क्वार्टर की मरम्मत और नवीनीकरण की भी मांग की।

अन्य मांगों में लड्डा पंचायत–ए और बी में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार और मौंगरी और लड्डा में जम्मू–कश्मीर बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं खोलना शामिल था।

डीसी ने सभी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके शीघ्र निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उठाई गई समस्याओं का प्रत्यक्ष आकलन करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी वास्तविक शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर और निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान किया जाए।

सभा को संबोधित करते हुए, डीसी ने जनता की सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस तरह के आउटरीच शिविरों के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोगों के बहुआयामी मुद्दों और विकासात्मक जरूरतों को समझना और उनके शीघ्र समाधान को सुविधाजनक बनाना है।

उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि सभी वास्तविक शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा।

प्रत्यक्षदर्शी ने उत्तरदायी, पारदर्शी और जन–केंद्रित शासन पर जोर देते हुए अधिकारियों से समर्पण, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी विभागों को अपने–अपने क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लाभार्थी अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें।

अंडर–17 बालिका बैडमिंटन में जम्मू बना चौंपियन, फाइनल में उधमपुर को 2–0 से हराया

कठुआ, 15 अक्टूबर। कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित संभाग स्तरीय अंतर–जिला अंडर–17 बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता में जम्मू जिले की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली। बुधवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जम्मू ने उधमपुर को सीधे दो सेटों में 2–0 से हराकर खिताब जीता।

फाइनल से पहले खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में उधमपुर ने पुंछ को 2–0 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई जबकि जम्मू की टीम ने रामबन को 2–0 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के समापन पर गतिविधि प्रभारी एस. धर्मेंद्र सिंह ने परवीन सिंह लखनपुरिया के साथ विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफियां प्रदान कीं। प्रतियोगिता में संभाग के विभिन्न जिलों की खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा, अनुशासन और खेल भावना का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता ने युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और खेल कौशल को निखारने का अवसर प्रदान किया। युवा सेवा एवं खेल विभाग की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जिले और संभाग में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ उभरती प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाना है। विभाग के अनुसार अंडर–14 बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन 16 अक्टूबर से शुरू होगा।

विधायक डॉ. सुनील भारद्वाज ने मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रामनगर के अलंकरण समारोह में की शिरकत

विद्यालय के विकास हेतु अतिरिक्त 15 लाख रुपये देने की घोषणा

उधमपुर, 15 अक्टूबर (संजीव शर्मा)। मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल (एचएसएस), रामनगर द्वारा हाल ही में विद्यालय के नवनिर्वाचित छात्र पदाधिकारियों के अलंकरण हेतु एक सुव्यवस्थित समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का उद्देश्य छात्र नेतृत्व को औपचारिक रूप से जिम्मेदारियां सौंपना तथा विद्यालय में अनुशासन, नियमों के पालन और विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान में उनकी भूमिका सुनिश्चित करना था। रामनगर के विधायक डॉ. सुनील भारद्वाज ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. जगदीश मेहरा तथा विद्यालय की प्रधानाचार्य उर्वशी परिहार भी उपस्थित रहीं। समारोह में विद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

समारोह के दौरान डॉ. भारद्वाज ने नवनिर्वाचित छात्र पदाधिकारियों को सम्मानित किया तथा उन्हें ईमानदारी, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सेवा भावना के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी से उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों, सामूहिक कार्य भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास होता है। आज के छात्र नेता ही भविष्य में समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों तथा राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया और उनकी मेहनत, समर्पण एवं उपलब्धियों की सराहना की। इसके अतिरिक्त, डॉ. भारद्वाज ने संयुक्त निदेशक और प्रधानाचार्य के साथ विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित विज्ञान मॉडलों का निरीक्षण किया तथा विद्यार्थियों की रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच और नवाचार की प्रशंसा की। इस अवसर पर डॉ. भारद्वाज ने विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों तथा विद्यार्थियों के कल्याण के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ–साथ बेहतर आधारभूत सुविधाएं और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण सक्षम, जिम्मेदार और

उज्ज्वल भविष्य वाली पीढ़ी के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डॉ. सुनील भारद्वाज ने विद्यालय परिसर के सुधार एवं सौंदर्यीकरण के लिए अतिरिक्त 15 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की।

इससे पहले वे विद्यालय के पुराने भवन की मरम्मत के लिए 12.5 लाख रुपये स्वीकृत कर चुके हैं। इस प्रकार इन कार्यों के लिए कुल 27.5 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। इस घोषणा का विद्यालय की प्रधानाचार्य, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने स्वागत किया। डॉ. भारद्वाज ने विद्यालय परिसर में 4.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्माणाधीन नए भवन खंड की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय व्यवस्था, आधुनिक सुविधाएं और उन्नत शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सके। शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों एवं शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए डॉ. भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा और विद्यालयों के आधारभूत ढांचे पर किया गया निवेश समाज के भविष्य में निवेश है। उन्होंने रामनगर विधानसभा क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत बनाने तथा विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

अंत में, विद्यालय की प्रधानाचार्य उर्वशी परिहार ने संस्थान के विकास में विशेष रुचि लेने तथा शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग प्रदान करने पर डॉ. सुनील भारद्वाज का आभार व्यक्त किया। उन्होंने समारोह को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, समस्त स्टाफ और विद्यार्थियों का भी धन्यवाद किया।

माता आशापूर्णी मंदिर को समर्पित भजन की टीम सम्मानित, नवरात्रों में भजन के जरिए हो रहा मंदिर का प्रचार

कठुआ, 15 अक्टूबर। कठुआ के मुख्य बाजार स्थित प्राचीन माता आशापूर्णी मंदिर को समर्पित भजन 'माता मेरी आशा पूर्णिमा' रिलीज होने के उपलक्ष्य में एक्सेल कंप्यूटर सेंटर की ओर से भजन की टीम को सम्मानित किया गया। संस्थान के डायरेक्टर दीपक ने गायक बंटी अलवस्त, लेखिका डॉ. उषा मोगा और मंदिर के पुजारी पुलकित खजूरिया को माता रानी की चुनरी और सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर दीपक अग्रवाल ने कहा कि नवरात्रों के पावन दिनों में माता आशापूर्णी मंदिर को समर्पित यह भजन श्रद्धालुओं के बीच मंदिर की पहचान और महिमा को पहुंचाने का सराहनीय प्रयास है। भजन के माध्यम से प्राचीन मंदिर का प्रचार–प्रसार भी हो रहा है जिससे श्रद्धालु मंदिर के धार्मिक महत्व से जुड़ सकेंगे।

Created by Universal Document Converter

आपकी जरूरतों के हिसाब से लगातार बेहतर बन रहा है एआई+ स्मार्टफोन

सॉफ्टवेयर अपडेट से लेकर बेहतर आफ्टर–सेल्स सपोर्ट तक, एआई+ स्मार्टफोन ग्राहकों के अनुभवों और सुझावों के आधार पर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेस को बेहतर बना रहा है

श्रीनगर, अक्टूबर, 2026। एआई+ स्मार्टफोन ग्राहकों के सुझावों और उनके फोन इस्तेमाल करने के अनुभवों के आधार पर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेस में लगातार सुधार कर रहा है। ग्राहकों के रिव्यू, रोजाना फोन इस्तेमाल करने के तरीके और आफ्टर–सेल्स सपोर्ट के दौरान मिली जानकारी के आधार पर कंपनी कैमरे की स्थिरता, कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट, बेहतर टेस्टिंग और कस्टमर सपोर्ट में सुधार कर रही है। कंपनी का उद्देश्य सिर्फ ग्राहकों के लिए प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि उनके सुझावों के साथ मिलकर बेहतर अनुभव प्रदान करना है।

एआई+ स्मार्टफोन के अलग–अलग मॉडल्स को उनके डिजाइन, कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस और कीमत के लिए ग्राहकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। नोवा 2 नियो 5जी को बैटरी परफॉर्मेंस और किफायती कीमत के लिए पसंद किया गया है, जबकि नोवा 2 पॉवर 5जी को उसके ओवरऑल अनुभव और ड्यूल–टोन डिजाइन, खासकर ब्लू फ्यूजन कलर के लिए सराहना मिली है। नोवा 2 अल्ट्रा 5जी को फोटोग्राफी, परफॉर्मेंस और एमोलेड डिस्प्ले के लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इसी तरह, नोवा 2 5जी और नोवा 2 प्रो 5जी को उनके ओवरऑल अनुभव और वैल्यू फॉर मनी के लिए पसंद किया गया है, जबकि एआई+ पल्स 2 को बैटरी, डिस्प्ले और डिजाइन के लिए सराहा गया है।

अच्छे रिव्यू के साथ–साथ, एआई स्मार्टफोन ग्राहकों के सुझावों के आधार पर उन क्षेत्रों की भी पहचान कर रहा है, जहाँ सुधार की जरूरत है। कैमरे की स्थिरता, कनेक्टिविटी और फोन की परफॉर्मेंस से जुड़ी समस्याओं को प्रोडक्ट और टेक्निकल टीमों के साथ साझा किया जा रहा है। इनके आधार पर ओवर–द–एयर (ओटीए) अपडेट और प्रोडक्ट में जरूरी सुधार किए जा रहे है। उदाहरण के लिए, नोवा 2 अल्ट्रा 5जी में कैमरे की स्थिरता बेहतर करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट दिए गए है। आने वाले फोन को बेहतर बनाने के लिए प्रोडक्ट रिव्यू और लॉन्च से पहले की टेस्टिंग में भी ग्राहकों के इन सुझावों को ध्यान में रखा जा रहा है।

एआई+ स्मार्टफोन ने प्रोजेक्ट ओपन रिव्यू के माध्यम से लॉन्च से पहले अपने फोन की स्वतंत्र जाँच कराने की पहल भी शुरू की है। इसके तहत बाहरी लोगों को फोन बाजार में आने से पहले उसकी जाँच करने और अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब तक इस पहल के लिए 1,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें रिव्यूअर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, पत्रकार, टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वाले लोग और पहली बार एथिकल हैकर्स भी शामिल हैं। इस पहल से कंपनी को बिना किसी तय स्क्रिप्ट के सीधे और ईमानदार सुझाव मिलते है, जिनके आधार पर लॉन्च से पहले जरूरी सुधार किए जा सकते हैं। यह पहल पारदर्शिता के जरिए ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने की कंपनी की सोच को बखूबी दर्शाती है।

इस बारे में बोलते हुए, एआई+ स्मार्टफोन के ब्रांड, मार्केटिंग और ग्रोथ हेड आर्ची गोगोई ने कहा, "एआई+ स्मार्टफोन में हमारा मानना है कि बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने की शुरुआत उन लोगों की बात सुनने से होती है, जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्राहकों के सुझाव हमें समझने में मदद करते हैं कि हम क्या सही कर रहे है और कहाँ सुधार की जरूरत है। चाहे सॉफ्टवेयर अपडेट हों, प्रोडक्ट की बेहतर टेस्टिंग हो या आफ्टर–सेल्स सपोर्ट, हमारा ध्यान ग्राहकों से मिली जानकारी के आधार पर जरूरी सुधार करने पर है। जैसे–जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम चाहते है कि हमारे ग्राहकों को यह भरोसा रहे कि एआई के अनुभव को बेहतर बनाने में उनकी राय की अहम् भूमिका है।"

कंपनी आफ्टर–सेल्स सर्विस को बेहतर बनाने के लिए हर दिन ग्राहकों के फीडबैक ले रही है,

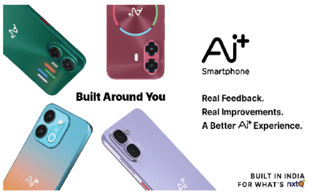

शिकायतों को ट्रैक करने का तरीका सुधार रही है और कस्टमर सपोर्ट व टेक्निकल टीमों के बीच तालमेल बढ़ा रही है। लॉन्च से पहले संभावित समस्याओं की पहचान के लिए अलग टीमें टेस्टिंग करती है। वहीं, ग्राहकों से बातचीत के दौरान सामने आने वाली सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्याओं को भी दूर किया जा रहा है। अगर स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण फोन की मरम्मत में देरी होती है, तो जहाँ जरूरी और संभव हो, ग्राहक को दूसरा हैंडसेट दिया जाता है, ताकि उसे कम से कम परेशानी हो।

ग्राहकों को जल्दी और उनकी जरूरत के हिसाब से मदद देने के लिए एआई स्मार्टफोन ने सोशल मीडिया पर मिलने वाले फीडबैक और शिकायतों पर कार्रवाई की प्रक्रिया को भी बेहतर बनाया है। अलग टीमें ग्राहकों के मैसेज, कमेंट्स और कंपनी को टैग करने वाली पोस्ट पर नियमित नजर रखती है। इससे शिकायतों को समझने, जरूरी मामलों को प्राथमिकता देने और समय पर कार्रवाई के लिए कस्टमर सर्विस टीम के साथ तालमेल बनाने में मदद मिलती है।

खरोट के काली माता मंदिर में विकास कार्यों की शुरुआत, डॉ. भारत भूषण ने रखी 10 लाख रुपये की आधारशिला

कठुआ, 15 अक्टूबर। कठुआ विधानसभा क्षेत्र के ऊपरी खरोट स्थित प्रसिद्ध काली माता मंदिर में विकास कार्यों की शुरुआत करते हुए विधायक डॉ. भारत भूषण ने 10 लाख रुपये की अनुमानित लागत से होने वाले कार्यों की आधारशिला रखी। इन कार्यों के लिए विधायक की विधानसभा क्षेत्र विकास निधि से धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका उद्देश्य मंदिर परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करना है।

काली माता मंदिर क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है जहां वर्षभर श्रद्धालुओं का आना–जाना लगा रहता है। विशेष रूप से नवरात्रों और नववर्ष के पहले दिन मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते है। ऐसे में मंदिर परिसर में आवश्यक विकास कार्य होने से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर विधायक डॉ. भारत भूषण ने धार्मिक स्थलों के संरक्षण और वहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक

सुविधाएं उपलब्ध करवाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कठुआ विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास तथा लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करवाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि विकास कार्य निर्धारित समय में पूरे किए जाएंगे जिससे मंदिर में आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी राजेश कुमार, पूर्व मुख्य योजना अधिकारी देविंदर सिंह, ग्रामीण विकास विभाग के कनिष्ठ अभियंता, वी–रामजी योजना के कार्यक्रम प्रबंधक, मंडल अध्यक्ष सुमन बाला, शमा जसरोटिया, कैप्टन पवन शर्मा, राज सिंह, धर्म सिंह, अनिरुद्ध शर्मा, अमित शर्मा, भानु प्रताप सिंह सहित गांव के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कठुआ में 'बदलाव' संगठन का आगाज–बिजली दरों राशन कार्ड और स्थानीय रोजगार के मुद्दे उठाएगा

कठुआ, 15 अक्टूबर। कठुआ में जनसमस्याओं के समाधान और जनहित की आवाज बुलंद करने के उद्देश्य से युवा नेता सक्षम कौशल ने सामाजिक संगठन 'बदलाव ए स्टेप टुवर्ड्स चेंज' की शुरुआत की। वीरवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि संगठन आम लोगों को होने वाली असुविधाओं और अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएगा। यह गैर–राजनीतिक मंच होगा जिसका मुख्य उद्देश्य कठुआ के लोगों का कल्याण है।

सक्षम कौशल ने बताया कि संगठन प्राथमिकता के आधार पर बिजली दरों में बढ़ोतरी, पात्र गरीब परिवारों के राशन कार्ड बहाल करवाने और घाटी स्थित सिडको औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दिलाने के मुद्दे उठाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन जल्द ही जिले के प्रत्येक वार्ड और पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों की समस्याएं दर्ज करेगा और उनके समाधान के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करेगा। इस अवसर पर संदीप सिंह ने लोगों से संगठन से जुड़कर जनहित के प्रयासों में सहयोग देने की अपील की। पत्रकार वार्ता में अमनदीप, सुनील, सुधांशु और ऋषव भी मौजूद रहे।

एसबीआई कार्ड और इटर्नल ने सह–ब्रांडेड 'इटर्नल एसबीआई कार्ड' लॉन्च किया

जोमैटो, बिस्ट्रो, डिस्ट्रिक्ट और ब्लिंकिट (कुछ चुनिंदा खर्चों) पर 10 प्रतिशत की तत्काल छूट

कार्डधारकों को उबर, इक्सिगो, अर्बन कंपनी और अपोलो 24/7 जैसे साझेदारों पर खर्च करने पर 5 प्रतिशत कैशबैक भी मिलेगा

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 2026। भारत में केवल क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली सबसे बड़ी कंपनी, एसबीआई कार्ड और इटर्नल लिमिटेड (जिसे पहले जोमैटो लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ने आज इटर्नल एसबीआई कार्ड को लॉन्च करने और इसके लिए 'अर्ली एक्सेस' ('पहले पहुँच') की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। यह एक सह–ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, जिसे इटर्नल और इससे जुड़ी कंपनियों की सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है। यह इस श्रेणी के शुरुआती कार्डों में से एक है, जो एक ही इकोसिस्टम के अंतर्गत कई ब्रांडों पर तुरंत छूट प्रदान करता है। इससे ग्राहकों को रोजमर्रा की खरीदारी पर अधिक लाभ मिलेगा और इटर्नल समूह के ब्रांडों के अलावा भी कई अन्य लाभ प्राप्त होंगे। ग्राहक अब जोमैटो, ब्लिंकिट और डिस्ट्रिक्ट ऐप्स के माध्यम से पहले आवेदन करने के लिए अनुरोध कर सकते है। 22 अक्टूबर 2026 से चरणबद्ध तरीके से कार्ड उपलब्ध होने पर उन्हें आवेदन करने के लिए आमंत्रण भेजा जाएगा।

कार्डधारकों को जोमैटो, डिस्ट्रिक्ट और ब्लिंकिट पर किए गए लेन–देन पर 10: की तत्काल छूट मिलेगी। ब्लिंकिट पर इलेक्ट्रॉनिक्स और ब्यूटी श्रेणियों के उत्पादों की खरीदारी पर

10 प्रतिशत और अन्य सभी श्रेणियों की खरीदारी पर 5 प्रतिशत की तत्काल छूट मिलेगी (नीचे दी गई कुछ अपवर्जित श्रेणियों को छोड़कर)। इन सभी छूटों की कुल सीमा उपर्युक्त सभी प्लेटफॉर्म पर की गई खरीदारी के लिए रु2,000 प्रति माह होगी। इसके अतिरिक्त, बिस्ट्रो पर 10: की तत्काल छूट और डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से मूवी टिकट खरीदने पर एक के साथ एक टिकट मुफ्त का ऑफर मिलेगा। (इटर्नल के ब्रांडों पर मिलने वाली सभी छूटें इन प्लेटफॉर्म पर पहले से उपलब्ध ऑफर के अतिरिक्त होंगी।) इटर्नल एसबीआई कार्ड के माध्यम से ग्राहक अपोलो 24द्य7, इक्सिगो, उबर और अर्बन कंपनी पर खर्च करने पर 5 प्रतिशत कैशबैक भी कमा सकते है। इस कैशबैक की अधिकतम सीमा रु1,000 प्रति माह होगी। इटर्नल एसबीआई कार्ड में कैशबैक स्वत: खाते में जमा होने की सुविधा भी है। इसके तहत, स्टेटमेंट तैयार होने पर पात्र लेन–देन पर मिलने वाला कैशबैक सीधे एसबीआई कार्ड खाते में अपने आप जमा हो जाएगा।

एसबीआई कार्ड की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सलिला पांडे ने कहा, "एसबीआई कार्ड हमेशा से अपने ग्राहकों की अलग–अलग जीवनशैली और पसंद के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहा है, ताकि उन्हें अधिकतम लाभ और बेहतर अनुभव मिल सके। इटर्नल के साथ रणनी. तिक साझेदारी में इटर्नल एसबीआई कार्ड की शुरुआत इसी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ग्राहकों की रोजमर्रा की खर्च संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया यह कार्ड कई श्रेणियों में आकर्षक कैशबैक लाभ, सुविधा और बेहतर मूल्य प्रदान करता है। इस कार्ड की शुरुआत से हमारे खुदरा सह–ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को और मजबूती मिलेगी।"

इटर्नल के मुख्य वित्तीय अधिकारी, अक्षांत गोयल ने कहा, "हर दिन का अधिकतम लाभ उठाएँ" इसी मूल सोच पर इटर्नल एसबीआई कार्ड तैयार किया गया है। हमारे ग्राहक. ों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके बार–बार होने वाले लेन–देन के माध्यम से उन्हे अधिक लाभ देने की अच्छी संभावना है। जोमैटो, ब्लिंकिट और डिस्ट्रिक्ट को केंद्र में रखते हुए, यह कार्ड रोजमर्रा के इन खर्चों को एक ही इकोसिस्टम के अंतर्गत लाता है और इसके बाहर भी ग्राहकों को लाभ प्रदान करता है।"

मुख्य लाभों के अलावा, यह सह–ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इटर्नल के इकोसिस्टम से बाहर कुछ चुनिंदा खर्चों पर भी कैशबैक और रिवॉर्ड देता है। कार्डधारकों को रु499 के जॉइनिंग शुल्क का भुगतान करने पर स्वागत लाभ के रूप में 6 महीने की जोमैटो गोल्ड सदस्यता निःशुल्क मिलेगी। इसके अलावा, पिछले वर्ष में रु2,00,000 का वार्षिक खर्च पूरा करने पर कार्डधारक खर्च के आधार पर वार्षिक शुल्क में छूट का लाभ भी उठा सकते है। इस क्रेडिट कार्ड में प्रत्येक स्टेटमेंट अवधि के दौरान रु200 तक 1 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज से छूट की सुविधा भी दी गई है।

यह क्रेडिट कार्ड मास्टरकार्ड और रुपे (RuPay), दोनों नेटवर्क पर उपलब्ध है। ग्राहक पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से जोमैटो, ब्लिंकिट या डिस्ट्रिक्ट मोबाइल ऐप पर इसके लिए आवे. दन कर सकते है।

भारत के सबसे बड़े आईपीओ से पहले जियो ने खोला अगला रोडमैप, तीन ग्रोथ इंजन पर फोकस

आकाश अंबानी ने मोबिलिटी, होम और एंटरप्राइज–इंटरनेशनल को बताया जियो के तीन ग्रोथ इंजन

होम ब्रॉडबैंड बेस करीब 3 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य

चुनिंदा विदेशी बाजारों में अपनी टेक्नोलॉजी स्टैक को मॉनेटाइज करने की तैयारी

मुंबई, 15 अक्टूबर 2026। भारत के अब तक के सबसे बड़े प्च्व् से पहले जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपने अगले दौर की ग्रोथ का रोडमैप सामने रखा है। मुंबई में पत्रकारों के साथ बातचीत में जियो प्लेटफॉर्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी ने मोबिलिटी, होम और एंटरप्राइज–इंटरनेशनल को कंपनी के तीन बड़े ग्रोथ इंजन बताया। कंपनी का मानना है कि टेक्नोलॉजी, डिजिटल गेटवे और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर वह थ्ल्31 तक भारत की करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी में बड़ी भूमिका निभा सकती है।

आकाश अंबानी ने कहा, "हमारे बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हमारा ग्राहक है।" उन्होंने कहा कि जियो का फोकस हर भारतीय, हर घर और हर एंटरप्राइज को बेहतर और किफायती डिजिटल सेवाएं देने पर रहेगा। जियो के पास फिलहाल करीब 53.3 करोड़ कनेक्टिविटी ग्राहक है और कंपनी भारत के 60 प्रतिशत से ज्यादा डेटा ट्रैफिक को संभालती है।

मोबिलिटी में कंपनी अगले पांच वर्षों में करीब 34 करोड़ नए 4जी और 5जी ग्राहकों का बाजार देख रही है। आकाश के मुताबिक इसमें करीब 10 करोड़ ऐसे नए ग्राहक होंगे जो पहली बार मोबाइल कनेक्शन लेंगे, जबकि करीब 24 करोड़ ग्राहक 2जी से 4जी और 5जी की ओर बढ़ सकते हैं। एफवाए26 में जियो के नेट एक्टिव मोबाइल ग्राहक दूसरे नंबर के ऑपरेटर के मुकाबले करीब तीन गुना ज्यादा बढ़े।

होम ब्रॉडबैंड को कंपनी आने वाले वर्षों का बड़ा ग्रोथ इंजन मान रही है। जियो के अभी करीब 2.86 करोड़ फिक्स्ड ब्रॉडबैंड ग्राहक है और कंपनी इस बेस को आगे 10 करोड़ घरों तक ले जाना चाहती है। एफवाए26 में देश में जुड़े कुल नए फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शनों में करीब 67.5 प्रतिशत हिस्सेदारी जियो की रही। आकाश ने बताया कि कंपनी फाइबर के साथ अपनी वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए देश के 19,000 पिन कोड तक पहुंच बढ़ा रही है।

तीसरा ग्रोथ इंजन एंटरप्राइज और इंटरनेशनल कारोबार है। जियो भारत में करीब ध्5.1 लाख करोड़ यानी 56.8 अरब डॉलर का एंटरप्राइज डिजिटल सर्विसेज बाजार देख रहा है। आकाश के मुताबिक देश की लगभग 65 प्रतिशत बैंक शाखाएं जियो नेटवर्क से जुड़ी है।

जियो अपनी बनाई एंड–टू–एंड टेक्नोलॉजी स्टैक को चुनिंदा विदेशी बाजारों में भी मॉनेटाइज करना चाहता है। कंपनी की योजना सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने की नहीं, बल्कि ग्लोबल टेलीकॉम कंपनियों के साथ मैनेज्ड सर्विस पार्टनर के रूप में काम करने की है। आकाश ने कहा कि इससे भारत टेक्नोलॉजी आयातक से टेक्नोलॉजी निर्यातक बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

इससे पहले ईशा अंबानी ने जियो की शुरुआत और रिलायंस की कारोबारी सोच का जिक्र करते हुए कहा कि कंपनी लंबे समय की सोच, बड़े पैमाने, मजबूत एक्जीक्यूशन और वित्तीय अनुशासन पर भरोसा करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत उदय कोटक ने रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी और 1977 के रिलायंस आईपीओ को याद करते हुए की।

मुख्य कृषि अधिकारी जम्मू ने सीमावर्ती गांव का दौरा कर खराब हुई फसलों का किया निरीक्षण

आरएस पुरा। मुख्य कृषि अधिकारी जम्मू मनोहर लाल शर्मा के साथ–साथ जिला कृषि अधिकारी विस्तार विनोद

खजुरिया, उप मंडल कृषि अधिकारी आरएस पुरा अरुण कुमार जराल के साथ–साथ फसल बीमा योजना से संबंधित कंपनी के अधिकारियों ने गुरुवार को क्षेत्र के गांव कोटली अर्जुन सिंह, बडैयाल ब्राह्मणा लोअर के साथ–साथ अन्य पंचायत का दौरा कर पिछले दिनों ओलावृष्टि एवं बारिश के कारण खराब हुई फसलों का निरीक्षण किया। इस मौके पर क्षेत्र के किसानों ने कृषि अधिकारियों को बताया कि लगातार क्षेत्र में हो रही बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण उनकी धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने मांग करते हुए कहा कि खराब हुई फसलों का उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा जिन किसानों ने फसल का बीमा कराया हुआ है उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। इस मौके पर मुख्य कृषि अधिकारी मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि कृषि विभाग की टीम में लगातार गांव–गांव में पहुंचकर बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई फसलों का निरीक्षण कर रहे है। इसके अलावा राजस्व विभाग की टीमें भी लगातार सर्वे कर रही है ताकि किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो सके। इस मौके पर उपमंडल कृषि अधिक. ारी ने कहा कि पहले दिन से ही कृषि विभाग की टीमें गांव गांव में पहुंच रही है और खराब फसलों की जानकारी हासिल करने के साथ–साथ पानी की निकासी के प्रबंध करने संबंधी किसानों को जागरूक किया जा रहा है।

पिट–एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

कठुआ, 15 अक्टूबर। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कठुआ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कथित आदतन नशा तस्कर को प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग्स एंड

साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस पिट–एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान राजा पुत्र नशर दीन निवासी सौंखल तहसील डिंगाअंब जिला कठुआ के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित दो मामले थाना हिरानगर में दर्ज हैं। इनमें एफआईआर नंबर 120/2025 और एफआईआर नंबर 51/2026 शामिल हैं। दोनों मामले एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 8/21/22 के तहत दर्ज किए गए हैं। नशा तस्करी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने और आरोपी की कथित गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से कठुआ पुलिस ने उसके खिलाफ विस्तृत डोजियर तैयार कर हिरासत में लेने की सिफारिश डिविजनल कमिश्नर जम्मू को भेजी थी। इसके आधार पर डिविजनल कमिश्नर ने आरोपी के खिलाफ पिट–एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत वारंट जारी किया। इसके बाद 14 अक्टूबर को थाना हीरानगर की पुलिस टीम ने वारंट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और उसे जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि जिले में नशा तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।

एशियन गेम्स मेडलवीरों से मिले पीएम मोदी

बोले–जुनून जीत में बदले तो चमकता है न्यू इंडिया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के आइची–नागोया में आयोजित एशियाई खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। भारतीय दल ने कुल 85 पदक जीते, जिनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। हालांकि, तीन साल पहले हांगझोऊ में जीते गए ऐतिहासिक 106 पदकों की तुलना में यह संख्या कुछ कम रही, फिर भी 2026 का प्रदर्शन ऐतिहासिक था, क्योंकि यह एशियाई खेलों में भारत का अब तक का दूसरा सबसे सफल प्रदर्शन रहा।

15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान खिलाड़ियों ने उन्हें अपनी हस्ताक्षरित (साइन की हुई) जर्सी और हॉकी स्टिक भेंट की, साथ ही शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में हुए एशियाई खेल हमारे लिए कई मायनों में यादगार रहे है। इतने सारे पदक वीर और उन सबको एक साथ मिलना... ये कोई

मामूली बात नहीं है। ये बहुत सुखद एहसास होता है। आप सब युवा एथलीट इस बात के उदाहरण है कि जुनून जब जीत में बदलता है तो वो कैसे मेडल के साथ साथ चेहरे की चमक भी लेकर आता है। और देश तो चमकता ही है।

मोदी ने कहा कि हमारी पुरुष और महिला हॉकी, दोनों टीमें यहाँ मौजूद है; दोनों ही टीमों ने स्वर्ण पदक जीते है। खासकर हमारी महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में, हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार पदक जीतकर अपने ही पिछले रिकॉर्ड को दोहराया है। कबड्डी में, हमारी पुरुष और महिला, दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते है। इसी तरह, हमने तीरंदाजी में पाँच स्वर्ण पदक हासिल किए। हमने शूटिंग में शानदार प्रदर्शन देखा, और बॉक्सिंग तथा कुश्ती में भी बड़ी सफलताएँ हासिल की। हमारे खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड बनाए, और हमने 28 साल बाद वेटलिफ्टिंग में भी एक पदक जीता है।

उन्होंने कहा कि 1982 के बाद पहली बार, भारत ने मैराथन में सफलता हासिल की है। यह सचमुच बहुत खुशी की बात है। मै विशेष रूप से हमारी बेटियों की तारीफ करना चाहूंगा। भारत ने जो 85 पदक जीते है, उनमें से 38 पदक हमारी महिला खिलाड़ियों ने हासिल किए है, जिनमें 11 स्वर्ण पदक शामिल है। ये पदक केवल कुछ आंकड़े नहीं है; ये एक श्नए भारतश् की सशक्त तस्वीर पेश करते है। आज भारत उन खेलों में भी पदक जीत रहा है, जिनमें एशियाई खेलों के इतिहास में हमने पहले कभी कुछ नहीं जीता था–जैसे कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, सॉफ्ट टेनिस और सेलिंग (नौकायन) के कुछ इवेंट्स। हमारे खिलाड़ियों ने इन खेलों में पहली बार पदक जीतकर इतिहास रच दिया है... पिछले 12 वर्षों में, भारत ने अपने खिलाड़ियों और खेल इकोसिस्टम को समर्थन देने के लिए बहुत धैर्य, लगन और समर्पण के साथ काम किया है।

उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में, देश ने एक दूरदर्शी सोच के साथ लगातार और समर्पित प्रयास किए है। हमने एक अधिक पारदर्शी और आधुनिक खेल इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया की शुरुआत की, और समय के साथ इन पहलों का विस्तार भी किया है। खेलो इंडिया का विस्तार करने और खेल महासंघों को मजबूत बनाने के लिए, हमने 36,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की है। आज, पूरे देश में 1,000 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जा चुके है।

Created by Universal Document Converter

भारत के भविष्य से खिलवाड़

ए. सूर्यप्रकाश

लगता है कि भारत के आंत. रिक मामलों में हस्तक्षेप करने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई मोदी सरकार को अस्थिर करने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पश्चिमी देशों और वैश्विक संस्थाओं के समक्ष की गई अपील अब असर दिखाने लगी है। एक के बाद एक चुनावों में भाजपा को हराने में नाकाम रहने वाले राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यही राग अलापते रहे कि पश्चिमी देश भारत में श्लोकतंत्र की पुनर्स्थापनाश के लिए मदद नहीं कर रहे है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय ताकतों से भारत के घरेलू मामलों में दखल देने की इस शर्मनाक अपील को उस समय कोई खास तवज्जो नहीं मिली थी, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिमी देशों और खुद भारत के भीतर सक्रिय शक्तियों के बीच साठगांठ मजबूत होती जा रही है।

यह एक विचित्र दुर्योग है कि जब कांग्रेस ने देश में अराजकता को बढ़ावा देकर मोदी सरकार को अस्थिर करने की व्यापक मुहिम शुरू की, उसी दौरान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों एवं परंपराओं पर नसीहत देना शुरू कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उसे दो–टूक जवाब देकर बिल्कुल सही किया कि वह अपने काम से काम रखे। इतना ही नहीं, भारत ने इस एजेंसी को आईना भी दिखाया कि उसके पड़ोसियों पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोगों के दमन पर उसने कैसे आंखें मूंदें रखीं।

आखिर संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नसीहत देने की यह जुर्रत कहां से आई? इसके जिम्मेदार राहुल गांधी जैसे लोग ही है। राहुल गांधी की गैर–जिम्मेदाराना हरकतों की कोई सीमा नहीं रह गई है। इसी क्रम में वे दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क की भारत विरोधी भावनाओं के साथ सुर मिलाते दिखे। अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदाता स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस न मिलने पर तिलमिलाए मस्क ने जब अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर झुंझलाहट दिखानी शुरू की तो राहुल उनके साथ हो लिए।

इस मामले में वास्तविकता यह है कि मस्क की कंपनी भारत में नियमन के पैमानों को अभी तक पूरा नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने अपनी खीझ भारतीय उद्यमियों और सरकार पर उतारनी शुरू कर दी। इसमें राहुल उन्हें एक तरह से उकसाते नजर आए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी जब भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनमी बताया था तो राहुल ने उनसे सहमति जताने में देर नहीं लगाई थी, जबकि हकीकत यह है कि हाल में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को लेकर अपना अनुमान और बढ़ाया है। वह भी तब जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिरता एवं सुस्ती से जूझ रही है।

भारत को धमकाने से जुड़ी मस्क की मंशा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मस्क ने बोल. ीविया के निर्वाचित राष्ट्रपति को सत्ता से बेदखल करने के लिए अमेरिका को उकसाया था, क्योंकि बोलीवियाई राष्ट्रपति अपने लीथियम भंडार मस्क को औने–पौने दाम पर देने और इसके लिए लाइसेंस देने के पक्ष में नहीं थे। जब एक्स पर किसी यूजर ने मस्क को इस तख्तापलट की साजिश रचने का श्दोषीश ठहराया, तो उन्होंने बहुत अहंकार भाव से जवाब दिया कि श्हम जिसका चाहें तख्तापलट करेंगे, जिसे जो करना है कर ले।श तख्तापलट को लेकर मस्क की ऐसी दंभ से भरी स्वीकारोक्ति यही दर्शाती है कि कि स्टारलिंक लाइसेंस विवाद पर मोदी सरकार से उपजी उनकी हताशा और भारत में राहुल गांधी द्वारा पैदा की जा रही अस्थिरता को अलग–अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए।

मस्क और राहुल के बीच यह जुगलबंदी बहुत कुछ कहती है। इससे यह भी स्पष्ट है कि देसी उद्यमियों के विरुद्ध विषवमन करती रहने वाली कांग्रेस को मस्क जैसे विदेशी एवं बदमिजाज कारोबारी के लिए लाल कालीन बिछाने से भी कोई गुरेज नहीं, जिस व्यक्ति को सामान्य शिष्टाचार और मर्यादाओं का भान तक नहीं और जो मुकेश अंबानी को भारत का श्रीयल बासश यानी प्रधानमंत्री करार देने से संकोच नहीं करता। राहुल को इस मामले में कमल हासन से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने मस्क को आईना दिखाते हुए स्पष्ट किया था कि श्भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई उपनिवेश नहीं। हमारे यहां दुनिया का स्वागत है, परंतु अपने भविष्य का फैसला केवल भारत की जनता करेगी, पश्चिमी स्वार्थ, उनकी दोहरे रवैये वाली नीतियां या कोई देसी–विद. ेशी अरबपति नहीं।श

इस सबके बीच अमेरिकी डीप स्टेट की पैदाइश या फिर उससे प्रोत्साहित मानी जा रही काकरा. ेच जनता पार्टी यानी सीजेपी को कोई कैसे अनदेखा कर सकता है। मोदी सरकार में भारत का अभूतपूर्व विकास अमेरिकी डीप स्टेट को पच नहीं पा रहा और लगता है कि वह सीजेपी के रूप में अपने मोहरे के जरिये भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रच रहा है। ठीक वैसे ही, जैसे उसने बांग्लादेश और नेपाल में किया था। इस परिदृश्य में मोदी के एक अंधविरोधी वकील भी उभरते है, जिन्होंने एलान कर दिया कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का एकमात्र रास्ता सिर्फ और सिर्फ श्क्रांतिश है। उनके दिमाग में यह बात पूरी तरह शीशे की तरह साफ है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से मोदी को शिकस्त नहीं दे सकते।

उन्हें यह कहने में भी कोई संकोच नहीं कि इसमें भारी श्खून–खराबा होगाश, लेकिन इसके सिवा अब कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा है। कुल मिलाकर देश में एक जहरीला गठजोड़ उभर रहा है। इसमें एक तरफ अमेरिकी डीप स्टेट है, जिसने अपने प्यादे को सीधे भारत में उतार दिया है। दूसरी तरफ एलन मस्क है, जो अपनी मनमानी शर्तें न मानने वाले मुल्कों में श्तख्तापलटश तक की धमकियां देते है। तीसरी तरफ हताश–निराश राहुल गांधी है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते है। अंत में वे बदहवास वामपंथी आते है, जो अब कहीं भी सत्ता में नहीं बचे। वामपंथियों के साथ प्रतिशोध के भाव से भरे ऐसे वकील है, जो खून–खराबे से ही वांछित परिणाम निकालने को बेताब है। अब यह देश की जनता को तय करना है कि वे अराजकता फैलाने वालों का साथ देंगे या फिर देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी का?

राष्ट्रीय हितों के आड़े न आए राजनीति

हर्ष वर्धन त्रिपाठी

पिछले दिनों जब केरलम के विझिंजम बंदरगाह से निर्यात–आयात शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह बंदरगाह दुनिया की ओर खुलने वाला द्वार है। खास बात यह है कि इस बंदरगाह का निर्माण अदाणी समूह ने किया है। यह भारत का गहरे समुद्र में बना ऐसा बंद. रगाह है, जिसकी देश को वर्षों से रणनीतिक आवश्यकता थी। 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के. करुणाकरन ने विझिंजम में एक डीप–सी बंदरगाह की परिकल्पना की थी। हालांकि कुछ रिकार्ड कहते हैं कि 1940 में त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर ने यह विचार सुझाया था और इसके आधार पर सर्वेक्षण भी हुआ था। परिकल्पना 1940 की मानें या 1991 की, इतना तो स्पष्ट है कि लंबे समय तक यह परियोजना कागजों में ही रही। जब इसके आकार लेने की बात आई तो प्रश्न उठा कि विझिंजम का डीप–सी पोर्ट बनाएगा कौन, क्योंकि 1995, 2004, 2008 और 2010 में चार प्रयासों के बाद भी कोई कंपनी इसे बनाने का ठेका नहीं ले सकी।

भारत में परियोजनाओं को धरातल पर लाने में अक्सर देरी होती ही है, लेकिन इस परियोजना में हुई देरी से देश को कितना नुकसान हुआ, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। भारत अभी तक अपने कंटेनर ट्रैफिक का 75 प्रतिशत कोलंबो, सिंगापुर और दुबई के बंद. रगाहों के जरिये लाता और

भेजता है। अब विझिंजम बंद. रगाह से निर्यात–आयात शुरू होने से भारत के जहा. जों की विदेशी बंदरगाहों के उपयोग पर निर्भरता कम होगी। गहरे समुद्र में बने विझिंजम बंदरगाह की गहराई स्वाभाविक तौर पर बिना खोदाई किए 20 मीटर की है। इसे आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि जहां विझिंजम बंदरगाह है, वहां समुद्र में लगभग 9–10 मंजिला इमारत पानी के भीतर समा जाएगी। प्राकृ तिक रूप से इतनी गहराई पर होने से विझिंजम बंद. रगाह में नियमित रखरखाव की लागत भी कम रहेगी। गहराई में होने के कारण विझिंजम बंदरगाह बहुत बड़े जहाजों को भी समायोजित–संचालित करने की क्षमता रखता है।

विश्व की बदलती रणनी. तिक परिस्थितियों में आपूर्ति शृंखला बनाए रखने की चुनौती भारत जैसे विशाल देश के सामने बहुत बड़ी है। विश्व के सामने विझिंजम बंदरगाह भारत के मजबूत होते अंतरराष्ट्रीय समुद्री बुनियादी ढांचे का बड़ा प्रमाण है। विश्व के सर्वाधिक व्यस्ततम पूर्व–पश्चिम समुद्री मार्ग के निकट होने से विझिंजम बंदरगाह के जरिये भारत वैश्विक व्यापार के केंद्र में आ सकता है। इस बंद. रगाह से निर्यात–आयात होने का सीधा लाभ देश के छोटे और मझोले उद्योगों को होगा। छोटे–मझोले उद्योगा. े के वैश्विक व्यापार में बने रहने के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है कि कम लागत में समय से उनका सामान पहुंचाया और मंगाया जा सके। विझिंजम बंदरगाह छोटे–मझोले उद्योगों के लिए यह करने जा रहा है। भारत के समुद्री उत्पादों, इंजीनियरिंग उत्पादों, काजू, मसाले, कपड़े को वैश्विक बाजार में पहुंचने में आसानी होगी। निर्यात के साथ हमारे देश की आयातक कंपनियों को भी इससे लाभ होगा। अंतरराष्ट्रीय कारोबार के साथ ही केरल के अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक के उद्योगों को भी अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग से सीधे जुड़ने का लाभ होगा। बंदरगाह पर बड़े मालवाहक जहाजों की आवाजाही से इससे जुड़े ढेरों व्यापार बंदरगाह के आसपास विकसित होंगे।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह बंदरगाह बड़ी भूमिका निभाएगा, लेकिन यह याद रहे कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व जिस गहरे समुद्री बंदरगाह की परिकल्पना की गई थी और उसका सर्वेक्षण भी हो गया था, उस पर काम 2015 में जाकर शुरू हो पाया और 2024 में जाकर पहला चरण पूरा हो पाया और उस दौरान भी राहुल गांधी अदाणी पर हमला जारी रखे हुए थे। जबकि जिस दौरान केरलम में यह बंदरगाह बन रहा था, तब राज्य में वामपंथी और कांग्रेसी सरकारें ही रहीं। विझिंजम बंदरगाह से निर्यात–आयात शुरू होते समय कांग्रेस की सरकार है और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का यह कहना कि अब सबसे बड़ी चुनौती इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाकर भारत और केरलम से दुनिया को जोड़ने और अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने की है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और एक सबक भी दे जाता है कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में देरी और उस पर दलगत राजनीति से देश का नुकसान होता है और सभी दलों को इससे बचना चाहिए।

भारत विश्व समीकरणों में जिस तरह से अपनी स्थिति बेहतर कर रहा है, उसमें विझिंजम बंदरगाह जैसे बुनियादी ढांचे का विशेष महत्व हो जाता है। कई बार हम यह चर्चा विशेषज्ञों के जरिये सुनते हैं कि 1980 तक भारत और चीन लगभग बराबर ही थे, लेकिन हम ऐसी रणनीतिक परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में पीछे रह गए। दलगत राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, पर्यावरण के नाम पर पैदा की जाने वाली बाधाओं और विशेषज्ञता वाली बड़ी कंपनियों के न होने से हम पिछड़ते चले गए। अब हम चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करके भारत और उसके बीच का अंतर कम कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में राजनीतिक बाधा न आए।

कानूनों के दुरुपयोग से उपजा संकट

सिद्धार्थ मिश्रा

पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी कानून के दुरुपयोग एवं उनकी जटिलताओं से परेशान कारोबारियों को बड़ी राहत दी। नई व्यवस्था के अनुसार अब जीएसटी अधिकारी कारोबारियों को जीएसटी कानूनों का हवाला देकर गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें कोर्ट से आदेश लेना होगा।

इसमें संदेह नहीं कि देश में जीएसटी कानूनों का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन यह दुरुपयोग केवल जीएसटी कानून या किसी एक कानून तक सीमित नहीं रहा है और यह भी आवश्यक नहीं है कि दुरुपयोग अधिकारियों द्वारा ही किया गया हो, जनता द्वारा कानूनों के दुरुपयोग के मामले भी प्रायरू सामने आते रहते हैं।

कानून देश की नींव होते हैं और पूरे देश की सामा. जिक, राजनीतिक, आर्थिक और विधिक संरचना कानूनों पर ही आधारित होती है। कानूनों का निर्माण एक ओर नागरिक. ों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करने और दूसरी तरफ समाज और देश में शांति, सुरक्षा, अनुशासन, व्यवस्था, विकास और प्रगतिशीलता बनाए रखने के लिए किया जाता है।

कानूनों का निर्माण उनके ईमानदार एवं सच्चाई से उपयोग तथा अनुपालन के उद्देश्य से होता है, परंतु स्थिति तब विकट हो जाती है जब नेक नीयत से बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग होने लगता है। यह स्थिति देश में विधि के शासन पर स्थापित व्यवस्था के लिए न केवल गंभीर चुनौती पेश करती है, बल्कि उस अवधारणा को कमजोर कर उसके समक्ष विश्वास का संकट खड़ा कर देती है।

भारत में व्यक्तिगत विवादों में कानूनों का दुरुपयोग एक पुरानी समस्या है, लेकिन आज यह केवल कुछ व्यक्तिगत विवादों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह न्याय–प्रणाली, पुलिस–तंत्र और मुकदमेबाजी की संस्कृति से जुड़ा एक गंभीर संरचनात्मक संकट बन चुका है।

कानून का उपयोग अधिकारों और दायित्वों के ईमानदारी से क्रियान्वयन

के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन जब किसी कानून का प्रयोग दबाव डालने, प्रतिशोध लेने, लाभ–प्राप्ति के लिए या विलंब के एक औजार के रूप में होने लगे, तब उसका नैतिक और संवैधानिक संतुलन बिगड़ जाता है।

देश में लंबित मामलों, विचाराधीन कैदियों और अत्यधिक बोझिल आपराधिक न्याय–व्यवस्था ने कानूनों के दुरुपयोग के लिए अनुकूल स्थिति बनाई है। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के अनुसार, 30 जुलाई, 2026 तक कुल 4,99,11,920 मामले लंबित थे, जिनमें लाखों आपराधिक और सिविल विवाद थे। 31 दिसंबर, 2024 तक भारत की जेलों की क्षमता 4,53,769 थी, लेकिन वहां 5,11,542 कैदी बंद थे, यानी जेलें 112.7 प्रतिशत क्षमता पर चल रही थीं। इसी तारीख पर 3,71,440 कैदी विचाराधीन कैदी थे, जो कुल जेल–जनसंख्या का लगभग 72.6 प्रतिशत था।

भारत में सामान्यतरू लगभग हरेक कानून का दुरुपयोग होता है, मगर सर्वाधिक दुरुपयोग वैवाहिक, पारिवारिक, संपत्ति–विवादों और जाति– भेदभाव संबंधी विवादों में दिखता है। कई मामलों में गंभीर शिकायतें वास्तविक होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में शिकायतों का इस्तेमाल बदला, दबाव या समझौते के साधन के रूप में किया जाता है।

घरेलू विवाद, दहेज–संबंधी आरोप, संपत्ति पर कब्जे और पड़ोसियों के झगड़ों में झूठी प्राथमिकी दर्ज करने और गिरफ्तारी कराने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऐसे में मुकदमे का परिणाम चाहे जो हो, लेकिन प्रक्रिया–भर में प्रतिवादी को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक क्षति झेलनी पड़ती है।

यही कारण है कि दुरुपयोग की समस्या को केवल श्झूठे केसश कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। यह एक प्रकार से श्प्रक्रियात्मक दंडश की समस्या भी है। समस्या का एक मूल कारण गिरफ्तारी की अत्यधिक उपयोग–प्रवृत्ति भी है।

कई मामलों में पुलिस पहले हिरासत, फिर जांच के सिद्धांत पर काम करती है। इससे कानून के दुरुपयोग की आशंका बढ़ती है, क्योंकि गिरफ्तारी स्वयं एक दंड बन जाती है। नौकरी, प्रतिष्ठा, परिवार, कारोबार और मानसिक स्वास्थ्य–इन सब पर गिरफ्तारी का प्रभाव पड़ता है, भले ही बाद में व्यक्ति बरी हो जाए।

इस संकट का समाधान कानूनों को अधिक सटीक, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने में है। पहली आवश्यकता है गिरफ्तारी को अपवाद बनाना, न कि स्वचालित प्रतिक्रिया। दूसरी, झूठी, दुर्भावनापूर्ण या बदले की भावना से दायर शिकायतों पर क्षतिपूर्ति और उचित दंड को प्रभावी बनाना।

तीसरी, पुलिस और अभियोजन की प्रारंभिक जांच को अधिक विश्वसनीय बनाना, ताकि हर विवाद सीधे आपराधिक मुकदमे में न बदला जाए। चौथी, न्यायालयों की क्षमता बढ़ाकर लंबित मामलों को कम करना, क्योंकि देरी स्वयं दुरुपयोग की जमीन तैयार करती है। डिजिटल न्याय–प्रबंधन इस दिशा में उपयोगी हो सकता है।

यदि न्यायालय, पुलिस और अभियोजन के डाटा का नियमित विश्लेषण किया जाए, तो यह पहच. ाना जा सकता है कि कौन–से प्रविधान सबसे अधिक विवादास्पद हैं, किन क्षेत्रों में झूठे या कमजोर केस बार–बार दर्ज हो रहे हैं और कहां जमानत तथा विचाराधीनता का असंत. ुलन सबसे अधिक है।

पारदर्शिता दुरुपयोग को सीमित कर सकती है, क्योंकि कानूनों का दुरुपयोग अक्सर अंधेरे में पनपता है। डाटा–आधारित निगरानी और जवाबदेही से प्रणाल. ीगत दोषों की पहचान पहले ही संभव होती है।

Created by Universal Document Converter

घगवाल मुख्य चौक पर जोरदार भिड़ंत, ट्रक की टक्कर से क्रॉस बैरियर तोड़कर आगे निकला टाटा 710

घगवाल (निखिल पंगोत्रा)। जम्मू–पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग–44 पर घगवाल मुख्य चौक में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब ट्रक और टाटा 710 वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि टाटा 710 हाईवे पर लगाए गए सुरक्षा क्रॉस बैरियर को तोड़ते हुए आगे जा पहुंचा। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रक नंबर पीबी07सीजी–2967 और भारतीय डाक विभाग का टाटा 710 वाहन नंबर जेके02डीई–0750 दोनों कठुआ की ओर जा रहे थे। घगवाल मुख्य चौक के पास अचानक दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा–तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक की पहचान उमेश निवासी गांव कोठी, जिला होशियारपुर के रूप में हुई है, जबकि टाटा 710 चालक अशोक कुमार निवासी तालाब तिल्लो, जम्मू बताया गया है। सुरक्षा बैरियर ने टाला बड़ा खतरा

टक्कर के बाद टाटा 710 हाईवे किनारे लगे सुरक्षा क्रॉस बैरियर को तोड़कर आगे निकल गया। हादसे की तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी तेज थी। मौके पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था और बैरियर के कारण वाहन की रफ्तार नियंत्रित हुई, जिससे राहगीरों और अन्य वाहनों के लिए बड़ा खतरा टल गया। अगर वाहन बैरियर पार कर आगे बढ़ जाता और वहां से गुजर रहे राहगीरों या दूसरे वाहनों की चपेट में आ जाता, तो हादसा और गंभीर हो सकता था। दो युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया हादसे की सूचना मिलते ही आपातकालीन सेवा 112 की पुलिस गाड़ी मौके पर पहुंची। टाटा 710 में सवार दो युवकों को उपचार और चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है।

मौके पर दोनों वाहन चालकों ने दुर्घटना को लेकर अपना–अपना पक्ष रखा। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसका वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। व्यस्त चौक पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवाल घगवाल मुख्य चौक क्षेत्र में लिंक रोड, अस्पताल, मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की ओर जाने वाले लोगों की आवा. जाही रहती है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण यहां भारी वाहनों का दबाव भी बना रहता है। ऐसे में ट्रक की टक्कर से सुरक्षा बैरियर का टूट जाना स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। लोगों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे की स्थिति पैदा न हो। अब सवाल यह है कि क्या संबंधित विभाग इस घटना के बाद घगवाल मुख्य चौक की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की समीक्षा करेगा? या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी?

करनाह में जेकेटीजेएसी की जोनल इकाई गठित

मोहम्मद असलम लोन अध्यक्ष और फरीद खान मुख्य संरक्षक नियुक्त

करनाह। जम्मू–कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जोन तंगधार में संगठन को मजबूत बनाने और शिक्षकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से नई जोनल इकाई का गठन किया है। अधिसूचना के अनुसार, मोहम्मद असलम लोन को जोनल अध्यक्ष और मोहम्मद फरीद खान को मुख्य संरक्षक नियुक्त किया गया है। शफकत रशीद को उपाध्यक्ष तथा शमा नाज को महिला विंग की उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंजूर अहमद बधाना को महासचिव और आबिदा बशीर को महिला विंग का महासचिव नियुक्त किया गया है। अन्य नियुक्तियों में शकील हुसैन शाह को मुख्य आयोजक, आदिल इशाक को सचिव, रुबीना बानो को संयुक्त सचिव, राजा जमील अहमद खान को मुख्य प्रवक्ता और ताहिर बशीर वानी को उप प्रवक्ता बनाया गया है। शाजिया फारूक को महिला विंग की प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। वित्तीय मामलों के लिए परवेज

अहमद खान को मुख्य लेखाकार, ख्वाजा अब्दुल कय्यूम को सहायक लेखाकार और आरूसा फरीद को लेखाकार की जिम्मेदारी दी गई है। जफर इकबाल को प्रचार सचिव तथा सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह को मीडिया एवं प्रचार सचिव नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त मोहम्मद इदरीस बजाड़ को मुख्य संयोजक, अजमत रजाक को संयोजक, परवीन अख्तर को उप संयोजक, मोहम्मद जावेद कुरैशी को मुख्य सलाहकार और मोहम्मद इलियास मीर को कानूनी सलाहकार बनाया गया है। संगठनात्मक कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए विभिन्न सलाहकारों, कार्यकारिणी सदस्यों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

अधिसूचना में नौवान गबरा/हजीत्रा कंडी, तंगधार/ख्वारपारा तथा बाग बेला/नाचियां सहित विभिन्न क्षेत्रों के क्लस्टर प्रतिनिधियों और महिला विंग के पदाधिक. ारियों का भी उल्लेख किया गया है। संगठन ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी, समर्पण और अनुशासन के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने की अपील की है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य शिक्षकों की समस्याओं, मांगों और चिंताओं को संबंधित अधिका. रियों के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाना तथा संगठनात्मक गतिविधियों को अधिक मजबूत बनाना है।

निदेशक पर्यटन डा. विकास गुप्ता और सामाजिक कार्यकर्ता केशव चोपड़ा ने भक्ति भजन डेरा पाड्डुर लाया किया रिलीज

जम्मू। विशाल म्यूजिक द्वारा प्रस्तुत भक्ति भजन डेरा पाड्डुर लाया को आज पर्यटन निद. ेशक, जम्मू डॉ. विकास गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए रिलीज किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं संवेदना सोसायटी के अध्यक्ष केशव चोपड़ा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पंकज सासन, उप निद. ेशक पर्यटन, जम्मू; विशाल सदोत्रा, सहायक निदेशक पर्यटन, जम्मू; और ममता शर्मा, उप निदेशक पर्यटन (योजना), विशेष अतिथियों के रूप में उपस्थित थे, जबकि कमल गुप्ता, वरिष्ठ निजी सचिव, पर्यटन निदेशक, जम्मू, अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन संवेदना सोसाइटी द्वारा किया गया!

इस भजन में गायक विशाल शर्मा की मधुर आवाज है, जिसके गीत और रचना निर्भय सलाथिया द्वारा तथा संगीत डॉ. वी. कैथ द्वारा तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट का निर्देशन रवि शर्मा ने किया है, जबकि संपादन और कलर ग्रेडिंग धन. राज स्टूडियोज द्वारा की गई है। दानेश शर्मा और योगेश शर्मा कलाकारों के रूप में नजर आए है, और इस भक्ति प्रस्तुति को उस्ताद कृष्ण कुमार झोनी जी तथा गुरुजी श्री श्री 1008 सत्य दास जी भोनी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है।

इस अवसर पर बोलते हुए, डॉ. विकास गुप्ता ने इस पहल की सराहना की और कहा कि जम्मू में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, यहाँ के प्रतिभावान युवा विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान दे रहे है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पर्यटन विभाग हमेशा युवाओं के साथ खड़ा रहा है और ऐसी पहलों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि और रचनात्मक क्षमता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने जम्मू भर में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में पर्यटन विभाग की टीम के प्रयासों की भी सराहना की, और कहा कि इस तरह के प्रयास क्षेत्र की सुंदरता, विरासत और सांस्कृतिक पहचान को

उजागर करने में मदद करते है।

केशव चोपड़ा ने गायक, निर्देशक और इस भक्ति भजन के पीछे की पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि संवेदना सोसायटी हमेशा जम्मू–कश्मीर के युवाओं का समर्थन करने और प्रतिभावान युवाओं को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय कलाकारों को एक बड़े दर्शक वर्ग के सामने अपनी प्रतिभा लाने के लिए प्रोत्साहन और मंच मिलना चाहिए, और यह भी जोड़ा कि क्षेत्रीय संस्कृ ति, संगीत और भक्ति परंपराओं को बढ़ावा देना जम्मू–कश्मीर की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है।

चोपड़ा ने युवाओं से नशों से दूर रहने और अपनी ऊर्जा को रचनात्मकता, कड़ी मेहनत तथा सकारात्मक कार्यों में लगाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युवाओ. ं में अपार क्षमता है और वे अपनी प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करके तथा समाज में रचनात्मक योगदान देकर सफलता प्राप्त कर सकते है। उन्होंने युवा अधिकारिता, सांस्कृतिक संवर्धन और सामाजिक जागरूकता के प्रति संवेदना सोसायटी की प्रतिबद्धता को दोहराया, और युवाओं से यह संदेश अपनाने की अपील कीरू नशों को कहें ना और प्रतिभा को कहें हाँ।

डेरा पाड्डुर लाया का रिलीज होना भक्ति की भावना और स्थानीय कलाकारों तथा रचनात्मक पहलों को प्रोत्साहित करने के महत्व को दर्शाता है। इस अवसर पर जम्मू की कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने और क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने में सांस्कृतिक हितधारकों और सार्वजनिक संस्थानों के बीच सहयोग के महत्व को भी रेखांकित किया गया।

इस अवसर पर निर्भय सलाथिया, डॉ. वी. कैथ, रमन वैद्य, अमित कपूर, गौरव, अभिषेक गुप्ता और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

सांबा में अवैध खनन पर पुलिस का शिकंजा, छह वाहन जब्त; पांच डंपर भी शामिल

सांबा। सांबा जिले में अवैध खनन और निर्माण सामग्री की गैरकानूनी ढुलाई के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह वाहनों को जब्त किया है। जब्त वाहनों में पांच डंपर और एक ट्रैक्टर–ट्रॉली शामिल है।

पुलिस के अनुसार, थाना सांबा के अंतर्गत आने वाली मंसर, सुपवाल और गोरान पुलिस चौकियों की टीमों ने अपने–अपने क्षेत्रों में गश्त के दौरान यह कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपित गतिविधियों में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान डंपर संख्या जेके21जी–5946, जेके14एफ–0422, जेके21जी–7847, जेके21जी–5325 और जेके21जी–6611 जब्त किए गए। इसके अलावा जेके21जे–3780 पंजीकरण नंबर वाली ट्रैक्टर–ट्रॉली भी पुलिस के कब्जे में ली गई।

पुलिस ने सभी वाहनों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सांबा के भूविज्ञान एवं खनन विभाग को सौप दिया है। अब संबंधित विभाग मामले में नियमानुसार कार्रवाई करेगा।जिले में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और निर्माण सामग्री के गैरकानूनी परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

Printer, Publisher, Owner, Editor by: Sanktha Prasad Singh Published from: 1408, G H Skara, Near Ladakh Public School, Leh-Ladakh, Ladakh - 194101, Published from: Ladakh Imperial Printing press, Gh Skara, Near Ladakh Public School, Leh Ladakh, 194104, Mob.: Mob.: 9818069272, 8287390112, Email: ladakhtoday@gmail.com
**All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent courts and forums in Leh - city.

Created by Universal Document Converter